हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

वार्षिक योजना बजट

2024–25

के लिए

मानकीय विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु दिनांक 29 तथा 30 जनवरी, 2024 को माननीय मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों की कार्यवाही ।

योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002

विषय सूची

क्र. सं. / जिला	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	पृष्ठ
1.	2.	3.
प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, के स्वागत भाषण का संक्षिप्त विवरण ।		1
1. ऊना		
1.	गगरेट	1–2
2.	ऊना	2–3
3.	कुटलैहड़	3
2. हमीरपुर		
1.	भोरंज	3
2.	हमीरपुर	4
3.	बड़सर	4–5
3. सिरमौर		
1.	पच्छाद	5
2.	नाहन	5–6
4.	पावंटा	6
4. सोलन		
1.	नालागढ़	6–8
2.	कसौली	8–9
3.	सोलन	10
4.	अर्की	10
5.	दून	10
5. चम्बा		
1.	चुराह	10–11
2.	भरमौर	11–12
3.	चम्बा	12–13
4.	डलहौजी	13
6. बिलासपुर		
1.	झंडूता	14–15
2.	बिलासपुर	15
3.	श्री नैना देवी जी	16
7. लाहौल–स्पिती		
1.	लाहौल–स्पिती	16–17

8. काँगड़ा		
1.	नूरपुर	17–18
2.	इन्दौरा	18–20
3.	फतेहपुर	20–21
4.	देहरा	21–22
5.	जसवां–प्रागपुर	22
6.	ज्वालामुखी	22–23
7.	शाहपुर	23–24
9. कुल्लू		
1.	मनाली	24–25
2.	बन्जार	25
3.	आनी	25–26
10. शिमला		
1.	चौपाल	26–27
2.	ठियोग	27
3.	रामपुर	27–28
11. मण्डी		
1.	करसोग	28–29
2.	नाचन	29–30
3.	बल्ह	31
4.	सरकाघाट	32
मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार, का धन्यवाद प्रस्ताव ।		33
माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश ।		34–40
माननीय मुख्य मन्त्री का उद्‌घाटन भाषण (अनुबन्ध 'क')		41–43
दो दिवसीय बैठकों की जिलावार समय सारणी।		44
जिलावार / चुनाव क्षेत्रवार बैठकों में भाग लेने वाले माननीय मन्त्रियों एवं विधायकों का ब्यौरा ।		45–46

वार्षिक योजना 2024–25 की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए माननीय विधायकों के साथ दिनांक 29 तथा 30 जनवरी, 2024 को श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु, माननीय मुख्य मन्त्री, की अध्यक्षता में हुई बैठकों की कार्यवाही ।

....

सर्वप्रथम श्री देवेश कुमार, प्रधान सचिव (योजना) ने माननीय मुख्य मन्त्री, समस्त माननीय मन्त्रीगण, माननीय मुख्य संसदीय सचिवों, माननीय विधायकों, मुख्य सचिव, समस्त प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं अन्य उपस्थित अधिकारियों का वार्षिक बजट 2024–25 के लिए माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए आयोजित इस बैठक में स्वागत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि माननीय विधायकों के साथ विचार–विमर्श के लिए निर्धारित बैठकें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन बैठकों में माननीय विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों की प्राथमिकताओं के अतिरिक्त उनसे अन्य बहुमूल्य सुझाव भी प्राप्त होते हैं। यह सुझाव राज्य के आगामी वार्षिक बजट तैयार करने तथा प्रदेश के सन्तुलित एवं तीव्र विकास के लिए कारगर सिद्ध होते हैं। प्रधान सचिव (योजना) ने स्पष्ट किया है कि सम्बन्धित विभाग, विधायक प्राथमिकताओं की योजनाओं की प्रगति की जानकारी समय–समय पर विधायकों को उपलब्ध करवाते हैं तथा उनसे यह अपेक्षा है कि भविष्य में भी योजनाओं की जानकारी समय–समय पर उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। सभी माननीय विधायक आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अपनी विधायक प्राथमिकताओं को ऑनलाईन भी प्रेषित कर सकते हैं। माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं की योजनाओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में समय–समय पर मुख्य सचिव के स्तर पर इन योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया कि वह अपने स्तर पर नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें एवं कार्यों को गति प्रदान करें तथा यह भी अनुरोध किया कि सभी विभाग माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तुरन्त कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित माननीय विधायक एवं योजना विभाग को भी सूचित करेंगे। प्रधान सचिव (योजना) ने सभी प्रशासनिक सचिवों एवं विभागाध्यक्षों की ओर से इस बात का भी आश्वासन दिया कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों का तुरन्त एवं पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। उन्होंने इस बात से भी सभी माननीय विधायकों को अवगत करवाया कि वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक की ट्रांचिज़ (Tranches) नाबार्ड द्वारा बन्द की जा चुकी हैं। अतः इस अवधि की सभी विधायक प्राथमिकताएं जिनकी डी.पी.आर. नहीं बनी है समाप्त कर दी गई हैं। तत्पश्चात प्रधान सचिव(योजना) ने माननीय मुख्य मन्त्री से आग्रह किया कि वे अपने सम्बोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें।

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने उदघाटन भाषण **(अनुबन्ध–"क")** के उपरान्त चुनाव क्षेत्रवार बैठक का शुभारम्भ किया । जिला एवं चुनाव क्षेत्रवार दो दिवसीय बैठकों में उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र. सं.	**जिला / माननीय विधायक / निर्वाचन क्षेत्र / बैठक में उठाये गए मुद्दे**	**सम्बन्धित विभाग**
1.	**2.**	**3.**
	1. जिला ऊना	
	1. श्री चैतन्य शर्मा, गगरेट	
1	डी.ए.वी. दौलतपुर चौक तथा रा0व0मा0पा0 की कक्षाओं का संचालन दौलतपुर चौक के कॉलेज कैम्पस से एक साथ किया जा रहा है। रा0व0मा0पा0 का संचालन रा0प्रा0पा0 तथा रा0मा0पा0 दौलतपुर चौक से किया जा सकता है जिसके लिए अतिरिक्त भूमि भी उपरोक्त स्कूलों के पास है।	शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
2	सी.एच.सी. दौलतपुर को सी.एच. तथा पी.एच.सी. अमलैहड़ को सी. एच.सी. का दर्जा प्रदान किया गया है। इन दोनों स्तरोननत स्वास्थ्य संस्थानों के Augmentation के लिए एक सर्वे (thorough survey) किया जाए जिसके लिए भूमि भी उपलब्ध है ताकि सही तरीके से इनका कार्य किया जा सके। साथ ही ब्लड बैंक को भी पी.एच.सी. अमलैहड के साथ/से ही संचालित किया जा सकता है।	स्वास्थ्य विभाग

3	दौलतपुर पुलिस चौकी एट डंगोह को पुलिस थाना बनाया जाए तथा इसका संचालन डी.ए.पी. सर्कल के साथ दौलतपुर से किया जाए।	पुलिस विभाग
4	होशियारपुर तथा दौलतपुर सड़कों के दोनों तरफ Border Areas पर कण्डे (धर्मकांटा/Weight Machine) का प्रावधान किया जाए।	Excise & Taxation/ परिवहन/ उद्योग विभाग
5	ड्रग माफिया पर नकेल कसी जाए तथा क्षेत्र में Drugs deaddiction centres का निर्माण व संचालन हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत किया जाए तथा इस सेन्टर के लिए सरकारी भूमि भी गगरेट में उपलब्ध है।	पुलिस/ स्वास्थ्य विभाग / उपायुक्त ऊना
6	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP) के प्रपत्र में इंगित स्वास्थ्य, आयुर्वेदा, पशुपालन व इत्यादि योजनाओं के सम्बन्ध में विधायकों को अवगत नहीं करवाया जाता है। जिला स्तर पर विधायक को उसके द्वारा दी गई योजनाओं की वस्तुस्थिति से समय-समय पर अवगत करवाया जाना चाहिए।	SOMA Deptt./ सम्बन्धित विभाग
7	क्षेत्र में विद्यमान शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण किया जाए।	शिक्षा/ स्वास्थ्य विभाग
8	तहसील वेलफेयर का कार्यालय अभी भी अम्ब में चल रहा है इसके स्थान पर घनारी से ही इसका सुचारू संचालन किया जाए।	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
9	मतस्य के क्षेत्र में executing agency HPSIDC है इसे बदलकर लोक निर्माण विभाग किया जाए।	उद्योग (HPSIDC) / मतस्य विभाग
10	ट्रक यूनियनस के लिए नियमितीकरण (regularization) की पॉलिसी बनाई जाए।	उद्योग विभाग
2. श्री सतपाल सिंह सत्ती, ऊना		
1	जिला ऊना में रामलीला मैदान के सामने वाले Boy स्कूल के पुराने भवन को गिराकर नये भवन का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है। इस भवन निर्माण कार्य के लिए शेष धनराशि रुपये 3.50 करोड़ रु0 को जल्द जारी कर कार्य को अविलम्ब पूर्ण किया जाए।	शिक्षा / लोक निर्माण विभाग
2	मिनी सचिवालय ऊना के निर्माण कार्य के लिए शेष धनराशि को जल्द जारी कर कार्य को अविलम्ब पूर्ण किया जाए।	राजस्व विभाग
3	क्षेत्रीय अस्पताल ऊना के न्यू ओपीडी ब्लॉक के निर्माण कार्य के लिए शेष धनराशि को जल्द जारी कर कार्य को अविलम्ब पूर्ण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4	पी.एच.सी. पीरनिगाह बसोली के भवन निर्माण तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र जनकौर की शेष धनराशि को जल्द जारी कर कार्य को अविलम्ब पूर्ण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5	योजना विभाग द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY) के सम्बन्ध में Retaining Wall/Breast Wall से सम्बन्धित दिनांक 17.08.2023 को पत्र जारी किया गया है जिसके तहत इस मद में जारी धनराशि को जून, 2024 तक व्यय किया जाना निर्धारित है। इस समय-सीमा को जनहित में बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
6	स्वां नदी चैनेलाईजेशन लगभग 1200 करोड़ रु0 से दो चरणों में किया गया है। यहाँ पर हो रहे अवैध खनन से चैनेलाईजेशन को खतरा हो रहा है इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए।	Excise & Taxation/ परिवहन/ उद्योग विभाग (Geological Wing)
7	क्षेत्र में हो रही ओवरलोडिंग पर भी पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। इस पर रोक लगाने के लिए हिमाचल में टिप्पर का साईज फिक्स किया जाए साथ ही M Form में क्षमता (capacity) भी निर्धारित की जाए।	Excise & Taxation/ परिवहन/ उद्योग विभाग

8	क्षेत्र में हो रही लड़ाई / छुरेबाजी व अन्य अपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। छूरेबाजी की घटना में घायल व्यक्ति पर अस्पताल में फिर से हमला किया गया। इस तरह की घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाया जाए साथ लॉ एण्ड आर्डर को दुरूस्त किया जाए।	पुलिस विभाग
9	संतोषगढ़ क्षेत्र में सट्टे की दुकानों में महिला पुलिस कर्मचारी को बंधक बनाया गया था। इस बारे पुलिस उचित कार्यवाही करे ताकि आम जनता का पुलिस पर / सरकार पर भरोसा बने रहे।	पुलिस विभाग
	3. श्री दविन्द्र कुमार भुट्टो, कुटलैहड़	
1	डीएसपी कार्यालय के लिए बंगाणा में भवन उपलब्ध है अतः इसे ऊना के स्थान पर बंगााणा किया जाए।	पुलिस विभाग
2	सब जज कोर्ट ऊना, बंगाणा के नाम से चल रहा है, बंगााणा से ही इसका संचालन किया जाए जिसके लिए मिनी सचिवालय के भवन में पर्याप्त कमरें भी उपलब्ध हैं।	राजस्व विभाग
3	बंगाणा अस्पताल को आदर्श अस्पताल के रूप में सुदृढ़ किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4	गौ अभ्यारण्य का निर्माण पशु पालन विभाग के पास उपलब्ध 250 कनाल भूमि बरनोह/ बढ़ोह पर किया जाए।	पशु पालन विभाग
5	स्पोर्टस संघ की Diet को बढ़ाया जाए। स्पोर्टस के क्षेत्र में अच्छी पॉलिसी का निर्माण किया जाए।	युवा खेल सेवाएं विभाग
	2. जिला हमीरपुर	
	1. श्री सुरेश कुमार, भोरंज	
1	सीरखडड तथा कुनाह खडड का तटीयकरण किया जाए। साथ ही सीरखडड के तटीयकरण को एक बड़े प्रोजेक्ट के रूप में एक साथ पूरा किया जाए।	जल शक्ति विभाग
2	सीरखडड में हो रहे अवैध खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। साथ ही sensitive areas में खनन पर पूरी रोक लगाई जाए।	उद्योग विभाग (Geological Wing)
3	कुनाह खडड में 800 बीघा सरकारी भूमि की माईनिंग को रोका जाए।	उद्योग विभाग (Geological Wing)
4	कुनाह खडड में कॉलेज से 150 मीटर, पुल से 15 मीटर तथा पीने के पानी की योजना से 150 मीटर की दूरी पर लगे एक क्रशर के कारण उपरोक्त तीनों स्थानों को खतरा पैदा हो गया है कृपया इस पर पूर्ण रोक लगाई जाए/इसे बैन किया जाए।	लोक निर्माण/ जल शक्ति/उद्योग विभाग
5	भोरंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भोरंज क्षेत्र तथा टौणीदेवी क्षेत्र की सीमाओं पर लगती पंचायतों के सब–डिवीजन को ठीक किया जाए जैसे पुलिस थाना भोरंज है तथा तहसील टौणी देवी है। इन्हें दुरूस्त किया जाए।	उपायुक्त हमीरपुर/ राजस्व/ पंचायती राज/ ग्रामीण विकास विभाग
6	क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) में नियमों का सही प्रकार से पालन किया जाए ताकि आम जनता को कोई पेरशानी न हो।	लोक निर्माण विभाग
7	बस अडडा भोरंज के निर्माण के लिए हिमफैड की भूमि पर कृषि विभाग के स्टोर को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि शीघ्र कार्य आरम्भ हो सके।	बस अडडा प्राधिकरण / कृषि विभाग
8	सब डिवीजन भोरंज में मुख्यालय के उपर वाले स्कूल में सभी प्रकार के प्रशासनिक व अन्य कार्य सम्पन्न किए जाते हैं। यहॉं पर एक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण किया जाए।	शिक्षा विभाग
9	क्षेत्र में जाहू स्थान पर बनी गौशाला का सुदृढ़ीकरण किया जाए और नई गौशाला निर्माण के कार्य, जिसके लिए 25 कनाल भूमि चिन्हित की गई है को रोका जाए ताकि इस भूमि को किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग किया जा सके।	पशु पालन विभाग

2. श्री आशीष शर्मा, हमीरपुर		
1	हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र की गसोती खडड पर पुल निर्माण तथा कमलाह–सौरी सड़क की डी.पी.आर. को नाबार्ड से शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2	हमीरपुर में बन रहे शहीद स्मारक के लिए शेष धनराशि लगभग रू0 7 लाख का प्रावधान कर निर्माण कार्य तीव्रगति से पूर्ण किया जाए।	सैनिक कल्याण / लोक निर्माण विभाग
3	हमीरपुर शहर में Police Commandant Control Centre स्थापित किया गया है। इसके सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने लिए अतिरिक्त धनराशि लगभग रू0 30–40 लाख का प्रावधान पुलिस विभाग को करवाया जाए।	पुलिस विभाग
4	पॉलीक्लिनीक (Veterinary) हमीरपुर में खोला जाए।	पशु पालन विभाग
5	नालर्वी पंचायत के लिए कुनाह खडड पर पैदल पुल का निर्माण किया जाए जिसके लिए लगभग 2.50 करोड़ रू0 का भी प्रावधान सरकार द्वारा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6	हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र की कुछ पंचायतें भोरंज, टौणीदेवी सब–डिवीजन में पड़ती हैं इन्हें हमीरपुर सब–डिवीजन में शामिल किया जाए।	ग्रामीण विकास/ पंचायती राज/ राजस्व विभाग
7	मिनी सचिवालय / उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर के भवन का जीर्णोद्वार किया जाए।	उपायुक्त हमीरपुर
8	District Forensic Officer हमीरपुर में तैनात किया जाए।	State Forensic Science Laboratory
3. श्री ईन्द्र दत्त लखनपाल, बड़सर		
1	निर्वाचन क्षेत्र में जल शक्ति विभाग की बन्द पड़ी सिंचाई की योजनाओं को चालू कर किसानों के खेतों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।	जल शक्ति विभाग
2	गोविन्दसागर झील से सुरंग के माध्यम से क्षेत्र के लिए पानी की आपूर्ति की जा सकती है। इससे न केवल खडडों पर चैक डैम बनाकर खडडों के जलस्तर को ठीक किया जा सकता है बल्कि किसानों के खेतों को भी 24 घण्टे पानी उपलब्ध हो सकता है साथ ही क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।	जल शक्ति विभाग
3	निर्वाचन क्षेत्र में ट्रांसफार्मरज़, खम्बे, कन्डक्टर्ज़ की कमी को दूर किया जाए।	HPSEBLtd.
4	लिंक रोड़ की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। साथ ही सड़क के किनारे (वर्मे) भी पक्के कर ड्रेनेज सिस्टम को दुरूस्त किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5	पीएचसी भोटा 24x7 चलता है। इसे अपग्रेड किया जाए तथा इसमें स्टाफ नर्स व एमडी स्पैस्लिस्ट प्रदान किये जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
6	अस्थाई पुलिस चौकी बिझड़ी तथा भोटा को अपग्रेड/स्थायी किया जाए तथा बिझड़ी पुलिस चौकी को थाना बनाया जाए। साथ ही इनके लिए भवन की उचित व्यवस्था की जाए।	पुलिस विभाग
7	महाविद्यालय बड़सर में DP के पद को सृजित कर शीघ्र भरा जाए। ऑडिटोरियम तथा बाउन्ड्री वॉल का भी उचित प्रबन्ध किया जाए साथ ही MA (Engligh & Commerce) की कक्षाएं भी आरम्भ की जाएं।	शिक्षा विभाग
8	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बनी धंगोटा–पनयाली पीने के पानी की योजना के लिए रू0 35 लाख का प्रावधान किया जाए ताकि निर्माण कार्य पूर्ण कर क्षेत्र की जनता को इसका लाभ प्रदान किया जा सके।	जल शक्ति/ SOMA
9	निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं की डी.पी.आर. को नाबार्ड से शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण/ जल शक्ति विभाग

10	मिनी सचिवालय मैहरे के कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए रू0 3–4 करोड़ की धनराशि प्रदान की जाए।	राजस्व/ लो0नि0 विभाग
11	132 के.वी. सब–स्टेशन बड़सर को चालू किया जाए।	HPPTCLtd.
12	निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान सरकारी विद्यालयों में Toilets की पूर्ण स्वच्छता/ मुरम्मत सुनिश्चित की जाए। साथ ही स्कूलों के लिए दान में दिए गये पुराने/ जर्जर भवनों की मुरम्मत की जाए या नए भवनों का निर्माण किया जाए।	शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
	3. जिला सिरमौर	
	1. श्रीमति रीना कश्यप, पच्छाद	
1	पर्यटन की दृष्टि से हाब्बन वैली से चूरधार में रोपवे का निर्माण किया जाए।	पर्यटन/RTDC
2	पर्यटन की दृष्टि से शिरगुल महोदव की जन्म स्थली शाया मन्दिर, भुरेश्वर महादेव इत्यादि क्षेत्र में विद्यमान मन्दिरों को भी विकसित किया जाए।	पर्यटन/ भाषा कला एवं संस्कृति विभाग
3	सराहां अस्पताल को 100 बिस्तर किये जाने की अधिसूचना को निरस्त किया गया है इसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4	सराहन–चण्डीगढ़ सड़क की डी.पी.आर को शीघ्र तैयार किया जाए।	लोक निर्माण वि0
5	सोलन–मीनस सड़क को डबल लेन किया जाए तथा सनौरा से छोतर के भाग की दयनीय स्थिति को भी ठीक किया जाए।	लोक निर्माण वि0
6	3–4 विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली ओच्छघाट–नेरीपुल–छैला सड़क की दयनीय स्थिति को ठीक किया जाए तथा इसे डबल लेन बनाया जाए।	लोक निर्माण वि0
7	शहीद राजेश ठाकुर के नाम पर रा0व0मा0पा0 मानगढ़ का नाम रखा जाए।	शिक्षा विभाग
8	सराहन से तकाहन के लिए मिनी बस सेवा चलाई जाए।	HRTC/परिवहन विभाग
9	Replacement of old pumping machinery of WSS की योजना को शीघ्र नाबार्ड से स्वीकृत कर कार्य आरम्भ किया जाए।	जल शक्ति विभाग
	2. श्री अजय सोलंकी, नाहन	
1	मेडिकल कॉलेज नाहन के लम्बित कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए तथा कार्डियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट तथा स्टाफ नर्सिज़ के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
2	राजाओं के समय से सेना क्षेत्र में रह रहे लोगों को मकान मुरम्मत की भी अनुमति सेना से लेनी पड़ती है लोगों के रास्ते बन्द पड़े हैं इस Army-Civilian land despute (भूमि स्थानांतरण मामला) की समस्या को भारत सरकार के समक्ष उठाकर इसका हल किया जाए।	राजस्व विभाग/ उपायुक्त सिरमौर
3	नाहन के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा बाई पास सड़क के निर्माण में आ रही बाधा लगभग 300 मीटर सेना की भूमि अधिग्रहण / वैकल्पिक भूमि प्रदान करने के मामले में रू0 1.12 करोड़ जारी कर इस समस्या का समाधान कर शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	राजस्व / लोक निर्माण विभाग
4	अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP) के के तहत प्रदान की गई योजनाओं में पूर्ण बजट का प्रावधान कर इनका निर्माण कार्य पूरा किया जाए।	SOMA Deptt.
5	नाहन क्षेत्र के हकदार भूमिहीन लोगों को 2–3 बिस्वां भूमि प्रदान करने के कार्य में तेजी लाई जाए।	राजस्व विभाग
6	भेडों–आदबदरी सड़क के एफ.सी.ए. मामले को शीघ्र निपटाकर इसका निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	वन विभाग

7	नाहन निर्वाचन क्षेत्र में बन्द पड़े बस रूटों को चालू किया जाए और स्टाफ (ड्राईवर+कन्डक्टर) की कमी को दूर किया जाए। साथ ही नाहन लोकल शहर के लिए 2 मिनी बसें भी उपलब्ध करवाई जाएं।	HRTC / परिवहन विभाग
8	सुकेती फासिल पार्क को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
9	पेयजल की योजनाओं में फिल्टर नहीं हैं भविष्य में बनने वाली सभी योजनाओं में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही पुरानी योजनाओं में भी फिल्टर का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
	3. श्री सुखराम चौधरी, पौंटा	
1	हिमाचल तथा उतराखण्ड को जोड़ने वाली यमुना नदी के लगभग 25 कि0मी0 क्षेत्र की सीमा तय की जाए/बाउन्ड्री लगाई जाए, ताकि दूसरे राज्य वाले हिमाचल में खनन की गतिविधी न कर सकें।	राजस्व विभाग/ उपायुक्त सिरमौर
2	एफ.सी.ए. मामले में केन्द्र सरकार द्वारा कुछ तकनीकी आपत्तियां (AA&E and Sanction) लगाई जा रही हैं इनका शीघ्र समाधान किया जाए।	वन विभाग
3	हिमाचल तथा उतराखण्ड को जोड़ने वाले पुल का निर्माण उतराखण्ड सरकार द्वारा किया जा रहा है इसकी पूरी कनेक्टीविटी के लिए हिमाचल प्रदेश की ओर से केवल 1 कि0मी0 की सड़क का निर्माण किया जाना है जिसके लिए विभाग शीघ्र भूमि अधिग्रहण कर कार्य सड़क निर्मित करे।	लोक निर्माण विभाग
4	क्षेत्र के किसानों द्वारा बिजली के मीटर के लिए आवेदन की गई लम्बित फाईलों का शीघ्र निपटान कर मीटर प्रदान किए जाएं।	HPSEBLtd.
5	खेतों में सिंचाई के लिए 7 ईंच के लगभग 150 ट्यूबवैल लगाए गये हैं लेकिन मोटर नहीं लगाई गई हैं। इस विषय में किसानों को मोटर लगाने के लिए अधिकृत (authorize) किया जाए।	जल शक्ति विभाग
6	पाँवटा में पार्किंग का निर्माण अतिशीघ्र आरम्भ/पूर्ण किया जाए जिसके लिए भूमि भी उपलब्ध है।	लोक निर्माण/ शहरी विकास वि0
7	सड़क Balance work for the C/o Rajpur Nagheta Bharli Shiva Banore Km. 0/0 to 13/355 के लिए बोहरण नदी पर बनने वाले 25 मीटर पुल के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाकर शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ/पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8	बांगरण–सिंगापुरा–गोजर–खोदरी माजरी सड़क (CRIF) की मैटलिंग टारिंग करते समय इसकी उचित मोटाई का ध्यान रखा जाए क्योंकि इस क्षेत्र से औद्योगिक व खनन गतिविधियां होती हैं तथा भारी–भारी वाहनों को आना–जाना लगा रहता है।	लोक निर्माण विभाग
9	लालढांक–बदरीपुर–राजबन–शिलाई–रोहडू सड़क का निर्माण NHAI द्वारा किया जा रहा है। इसमें पौंटा–बदरीपुर चौक तक पानी के बड़े–2 drain pipe बनाकर बद्रीपुर चौक तक छोड़ दिया गया है, इससे आगे बदरीपुर से बाता पुल तक लगभग 4 कि0मी0 पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस पानी की निकासी को ड्रेन बनाकर बाता नदी में डाला जाए।	लोक निर्माण विभाग
10	पाँवटा अस्पताल में स्टाफ नर्सों की कमी को दूर किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
11	कालाअम्ब 440 के.वी. सब–स्टेशन बनकर तैयार है। इसे चालू किया जाए।	HPTCLtd.
	4. जिला सोलन	
	1. श्री के.एल. ठाकुर, नालागढ़	
1	नशे पर रोक लगाने के लिए डी.एस.पी. कार्यालय बददी का सुदृढ़ीकरण करने के साथ अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि उपरान्त स्थानांतरित भी किया जाए। यहाँ स्टाफ के पदों को बढ़ाया जाए तथा Special Task Force का भी गठन किया जाए।	पुलिस विभाग

2	अवैध खनन पर रोक लगाने के लीज को सैंकशन किया जाए और रात में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधियां न की जाएं। साथ ही Special Task Force का गठन किया जाए।	उद्योग विभाग (Geological wing)
3	आपदा से प्रभावित दभोटा पुल का निर्माण शीघ्र किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4	लोक निर्माण विभाग मण्डल की देनदारियों के लिए रू0 3 करोड़ का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5	जल शक्ति विभाग में फलैक्सी फण्ड रू0 2 करोड़ को जारी किया जाए।	जल शक्ति विभाग
6	राजकीय महाविद्यालय बरूना में खोला जाए।	शिक्षा विभाग
7	बीडीओ कार्यालय रामशहर में खोला जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
8	पूरे भारत में जल शक्ति विभाग के भीतर लघु सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा पेयजल के अलग–अलग प्रभाग (Wings/ Div.) कार्य करते है। उसी आधार पर हिमाचल में भी जल शक्ति विभाग के अलग–2 प्रभाग (Wings/ Div.) बनाए जाएं।	जल शक्ति विभाग
9	नालागढ़ क्षेत्र में 86 पद पैरा वरकर्ज़ के भरे जाने थे जिसमें से 26 ही दिए हैं कृपया पूरे 86 पदों को ही स्वीकृति प्रदान की जाए।	जल शक्ति विभाग
10	नालागढ़ शहर के लिए पेयजल योजना के लिए वर्ष 2024–25 में रू0 15 करोड़ का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
11	नालागढ़ क्षेत्र के मैदानी ईलाकों में भूमिगत पानी की कमी को दूर करने के लिए क्षेत्र के पहाड़ी ईलाकों की खडडों जैसे चिकनी, महादेव, कुण्डलू, लुहाण्ड की सहायक नदियों पर डैम बनाकर लघु सिंचाई की योजनाओं का प्रोजेक्ट बनाकर भारत सरकार के समक्ष फण्डिंग के लिए भेजा जाए।	जल शक्ति विभाग
12	गम्भर खडड पर काटल से गम्भर पुल की तरफ low height dams की परियोजना बनाकर भारत सरकार के समक्ष फण्डिंग के लिए भेजी जाए।	जल शक्ति विभाग
13	सरसा खडड और अन्य खडडों के तटीयकरण की रू0 1200 करोड़ की परियोजना को भी भारत सरकार से स्वीकृत करवाई जाए।	जल शक्ति विभाग
14	लिंक रोड़ ढेरोवाल–नालागढ़–रामशहर–कुनिहार–शिमला सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग किया जाए और जब तक यह राष्ट्रीय राजमार्ग नही होता है तब तक नालागढ़–रामशहर सड़क की दयनीय स्थिति को सी.आर.एफ. के अन्तर्गत ठीक किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
15	नालागढ़–स्वारघाट 4 लेन सड़क बनने के कार्य में तेजी लाई जाए तथा 10 कि0मी0 नालागढ़–दभोटा सड़क को भी इसमें शामिल किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
16	क्षेत्र में बने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना / अन्य योजना के तहत अनेक लिंक सड़कों की मुरम्मत के लिए उचित बजट का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
17	सड़कों की मैटलिंग व टारिंग की थिकनेस 30 एमएम से 25 एमएम की गई है इसे 30 एमएम व बीसी के साथ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
18	आपदा से खराब हुई पंचायतों की सड़कों को ठीक करने के लिए धनराशि स्वीकृत व जारी की जाए।	लोक निर्माण विभाग
19	क्षेत्र के लिए 75 ट्रांसफारमर्ज़ को जल्द स्थापित किया जाए।	HPSEBLtd.
20	विद्युत विभाग में तारों को Built up area से बदलने बारे उचित बजट का प्रावधान किया जाए।	HPSEBLtd./ HPTCLtd.
21	नालागढ़ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
22	नालागढ़ के दभोटा को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए।	उद्योग विभाग

23	नालागढ़ में मेडिकल / ईन्जीनियरिंग कॉलेज खोला जाए।	चिकित्सा शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा वि0
24	नालागढ़ के लिए दिए गये बस रूटस नालागढ़ से बददी, नालागढ़ से अमृतसर तथा नालागढ़ से वृन्दावन के लिए बस सेवाएं अविलम्ब आरम्भ की जाएं।	HRTC/परिवहन विभाग
25	नालागढ़ निर्वाचन क्षेत्र में फ्रूट तथा सब्जी प्रोसेसिंग प्लांट सरकारी या निजी क्षेत्र में स्थापित किया जाए।	कृषि/ उद्यान विभाग / Agriculture Marketing Board
26	बीबीएनडीए के अधीन क्षेत्र में विकास के लिए इस वर्ष रू0 35 करोड़ तथा अगले वर्ष के लिए 55 करोड़ रू0 बजट का प्रावधान किया जाए।	शहरी विकास / उद्योग विभाग
27	राजकीय महाविद्यालय रामशहर के भवन निर्माण हेतु इस वर्ष रू0 5 करोड़ तथा अगले वर्ष के लिए 7 करोड़ रू0 बजट का प्रावधान किया जाए और इसमें गणित व संगीत(Vocal) की कक्षाएं स्वीकृत की जाएं।	शिक्षा विभाग
28	हाल हीं में आपदा से प्रभावितों के मकानों को restore किया जाए।	राजस्व /ग्रामीण/ पंचायती राज वि0
29	पीएचसी जोघों और सब–हैल्थ सेन्टर पंजैहरा को पीएचसी में अपग्रेड किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
30	रामशहर तहसील के डोली में पीएचसी खोली जाए और सीएचसी नालागढ़ को 200 बिस्तर अस्पताल में अपग्रेड किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
31	पनवला (गनेड़) में नई राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोली जाए।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
32	रामशहर में नया अग्निशमन केन्द्र (Fire Sub-Station) खोला जाए।	अग्निशमन विभाग
33	सीएचसी रामशहर को 50 बिस्तर में स्तरोन्नत किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
34	रा0व0मा0 पाठशाला बघेरी में विज्ञान संकाय तथा रा0व0मा0 पाठशाला रतवाड़ी में वाणिज्य (Commerce) की कक्षाएं स्वीकृत की जाएं।	शिक्षा विभाग
2. श्री विनोद सुल्तानपुरी, कसौली		
1	नाहन सड़क से आगे जौहड़जी से मल्ला सड़क पिंजौर निकलती है इसे राज्य शीर्ष या केन्द्र के माध्यम से 5 मीटर चौड़ाई का बनाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2	औद्योगिक क्षेत्र काम्बली की सड़क को एनएच के साथ जोड़ा जाए।	लोक निर्माण विभाग
3	लोक निर्माण विश्राम गृह कोटी को एनएच के साथ जोड़ा जाए ताकि यहां पर जो 25 बीघा भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम है उसका सदुपयोग हो सके।	लोक निर्माण विभाग
4	परवाणु में टकसाल नामक स्थान पर रेलवे का फाटक है यहां पर फलाईओवर का निर्माण किया जाए ताकि औद्योगिक क्षेत्र की गाड़ियां आसानी से आवाजाही कर सकें।	लोक निर्माण/ परिवहन(रेलवे) विभाग
5	एनएच बनने से धर्मपुर बाजार उजड़ गया है अभी सुबाथु के लिए और अधिग्रहण होना है जिससे धर्मपुर बाजार पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहां पर एक बाईपास का निर्माण किया जाए जिसके लिए भूमि भी चयनित/देखी जा चुकी है।	लोक निर्माण विभाग
6	निर्वाचन क्षेत्र में कॉलेज का भवन लगभग तैयार है शेष कार्य को पूर्ण कर अगले सत्र 2024–25 से कक्षाएं आरम्भ की जाएं।	शिक्षा विभाग
7	बीडीओ कार्यालय का भी भवन लगभग तैयार है शेष कार्य को पूर्ण कर इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
8	कसौली में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोला जाए।	जल शक्ति विभाग
9	कौशल्या बाँध की डी.पी.आर. को नाबार्ड से स्वीकृत कर शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	जल शक्ति

10	एचआरटीसी की बसें जो 15 साल पुरानी हैं को ईलैक्ट्रिक व्हीकल में कनवर्ट करने बारे कार्य किया जाए जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता है।	HRTC
11	एचआरटीसी की बसों में real time base सुविधा प्रदान की जाए जिससे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को पता चल सके कि इस समय बस कहाँ पर है और कितनी देर में पहुंचगी इत्यादि। साथ ही क्षेत्रीय टैक्सियों को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है जिससे उन्हें भी त्वरित यात्री मिल सके।	HRTC
12	Parwanoo Industrial Association की मांग है कि जिस भूमि पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां/उद्योग स्थापित किए हैं उस भूमि का मालिकाना हक (ownership) उन्हें प्रदान करने बारे सरकार द्वारा कोई विशेष नीति बनाई जाए।	उद्योग विभाग
13	कालका शिमला रेल मार्ग पर पड़ने वाले स्टेशनों को थीम्स (Themes) (जैसे खाना, लेजर शो, फूल इत्यादि) के रूप में विकसित करने बारे रेलवे विभाग से तालमेल किया जाए ताकि यहां पर थीम ट्रेन चलाई जा सकें जिससे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा।	परिवहन (रेलवे) विभाग
14	सड़क दुर्घटना/ अन्य घटना में अस्पताल द्वारा मृत व्यक्ति का शव परिजनों को तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि दुर्घटना घटित क्षेत्र की पुलिस अस्पताल में नहीं पहुंचती। इस नियम का सरलीकरण / हल किया जाए।	पुलिस / स्वास्थ्य विभाग
15	विधायकों द्वारा / सांसदों द्वारा या अन्य किसी माध्यम से जब भी पंचायतों को धनराशि जारी की जाती है तो कार्य ही नहीं करते हैं। इनकी executing agency को बदलने बारे सरल नीति बनाई जाए और पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी न होने पर विकास कार्य किसी अन्य ऐजैन्सी से करवाने बारे नीति बनाए। साथ ही विधायकों के vision के अनुसार विकास कार्यों को किया जाए।	योजना विभाग/ समस्त उपायुक्त
16	माननीय मंत्री द्वारा रू० 20-20 लाख रू० की धनराशि अनुसूचित जाति की पंचायतें धर्मपुर तथा टकसाल को प्रदान की गई है जो उनके पास अव्ययित (unspent) पड़ी है जो वापिस (surrender) हो जाएगी। इस बारे विभाग कार्यवाही करे।	SOMA Deptt.
17	निजी लोगों द्वारा 10-10 मीटर की दूरी पर ही अपने पैसे से हैण्डपम्प लगाए जा रहे हैं जिससे भूमिगत जलस्तर में कमी आने से अन्य स्थानों में पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है इस बारे विभाग उचित कार्यवाही करे।	जल शक्ति विभाग
18	धर्मपुर स्टेशन पर बड़ा बस स्टैण्ड का निर्माण किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
19	धारा 118 के नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप क्षेत्र में कुछ भवन पाए गये हैं। इन भवनों को सरकार अपने अधीन लेकर उचित कार्यवाही करे / Auction/Sell करे।	उपायुक्त सोलन
20	त्रासदी के समय क्षेत्र की कुछ पंचायतों में लोगों के मकान धंस गये और भूमि अभी भी धंस रही है। साथ की अन्य पंचायतें उन लोगों की सहायता नहीं कर रही हैं। अतः उन प्रभावित लोगों की दुविधा को दूर करने हेतु एफआरए. के तहत उन्हे वन भूमि प्रदान की जाए ताकि वे लोग अपना घर बना सकें।	वन / राजस्व/ पंचायती राज/ ग्रामीण विकास विभाग
21	सुबाथु कॉलेज को सरकार ने अपने अधीन लिया है इसके स्टाफ की समस्या को हल किया जाए।	शिक्षा विभाग
22	हरियाणा से लगती सीमा टिम्बर ट्रेल के साथ बनासर में जो बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं इस बारे विभाग उचित कार्यवाही करे।	राजस्व विभाग

3. श्री धनी राम शांडिल, सोलन		
1	नशा निवारण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं और सरकार गाँव के द्वार मे भी इस सम्बन्ध में लोगों का सचेत किया जा सकता है या मैसेज के माध्यम से भी इस पर प्रचार व प्रसार किया जा सकता है। साथ ही स्कूलों में भी नशे के दुष्प्रभावों के बारे में Special drive तथा पाठ्यक्रम (lesson) के माध्यम से बताया जा सकता है, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी नशे को जड़ से उखाड़ फेंक सकती है।	शिक्षा/ पुलिस/ समस्त शैक्षणिक विभाग / समस्त सम्बन्धित विभाग
4. श्री संजय अवस्थी, अर्की		
1	वन विभाग द्वारा रिक्त/खाली पड़ी भूमि को DPF में convert किया जा रहा है। इस पर पूर्णतः रोक लगाई जाए।	वन/ राजस्व विभाग
2	मेरे क्षेत्र में वाईल्ड लाईफ एरिया है और आबादी बढ़ रही है लोग रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं। इस क्षेत्र को बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर वाईल्ड लाईफ से बाहर(exclude) किया जाए। साथ ही लोगों को इस बारे जागरूक भी किया जाए।	वन विभाग
3	एफआरए के मामले में डी.एफ.ओ. को कुछ प्रोजेक्ट/ योजनाओं में शक्तियां प्रदान की गई हैं इसमें शैक्षणिक संस्थानों (कॉलेज) को भी शामिल किया जाए।	वन / शिक्षा विभाग
4	खनन वाले क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित किया जाए नहीं तो हमारे लोग भूमिहीन हो रहे हैं। खनन एक तय सीमा तक होना चाहिए जैसे 10-15 साल उसके बाद उस भूमि का मालिकाना हक उसके परिवार को वापिस मिल जाना चाहिए।	राजस्व विभाग
5. श्री राम कुमार, दून		
1	विधायक प्राथमिकता के अधीन दिये जाने वाली सड़कों में लम्बाई तय की जाए। साथ ही पुरानी योजनाओं में पूरा बजट प्रदान किया जाए ताकि योजनाओं में टैण्डर लगाए जा सकें।	लोक निर्माण/ योजना विभाग
2	विधायक प्राथमिकता योजनाओं की डी.पी.आर. को निश्चित समयावधि में तैयार किया जाए।	लोक निर्माण/ जल शक्ति/समस्त सम्बन्धित विभाग
3	जल शक्ति डिवीजन बददी के अधीन 10 नं0 तथा 20 नं0 ट्यूबवैल की डीपीआर और 100 नं0 हैण्डपम्प की डीपीआर को तैयार कर शीघ्र स्वीकृत कर कार्य आरम्भ किया जाए।	जल शक्ति विभाग
4	वैलफेयर की योजनाओं में एकमुश्त बजट का प्रावधान किया जाए ताकि योजनाओं के टैण्डर कम से कम लगाए जा सकें।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता/ SOMA Deptts.
5	आईटीआई कुठाड़ तथा पटटा के भवनों के लिए उचित बजट प्रदान कर कार्य पूर्ण किए जाएं।	तकनीकी शिक्षा विभाग
6	बददी अस्पताल के लिए भी रू0 7 करोड़ का प्रावधान किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
7	सीएचसी भवन चण्डी के लिए रू0 13 करोड़ प्रदान किए जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
8	पीएचसी मानपुरा को खोला/ बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
9	बीडीओ कार्यालय पटटा को भी खोला/ बहाल किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
10	एसडीएम कार्यालय बददी को भी खोला/ बहाल किया जाए।	राजस्व विभाग
5. जिला चम्बा		
1. श्री हंस राज, चुराह		
1	राजधानी शिमला में हुई भयानक त्रासदी के दृष्टिगत 10-12 विभागों के मुख्यालयों को धर्मशाला स्थानांतरित किया जाए।	सामान्य प्रशासन
2	चम्बा को एनएच के माध्यम से जोड़ने के मुददे को लेकर गम्भीर रूप से कार्य कर चुवाड़ी टनल, पठानकोट से चम्बा, पांगी सड़क को भारतमाला में ही भारत सरकार से स्वीकृत करवाकर क्षेत्र का विकास किया जाए।	लोक निर्माण विभाग

3	विद्युत विभाग का डिवीजन तथा सब–डिवीजन नखरोड व तीसा में भौगोलिक स्थिति को देखेते हुए खोलने की रदद अधिसूचना को बहाल किया जाए।	HPSEBLtd. /सामान्य प्रशासन
4	विकास खण्ड चुराह/कोटी में खोलने की रदद अधिसूचना को बहाल किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग/ सामान्य प्रशासन
5	निर्वाचन क्षेत्र में खोले गये कॉलेज मसरूर को बन्द किया गया है इसे चालू किया जाए।	शिक्षा विभाग
6	निर्वाचन क्षेत्र में खोले गये तीन प्राथमिक स्कूलों (कोहालगढ़, ब्रुईला तथा लसोई) को बन्द किया गया है इन्हें पुनः चालू किया जाए। क्योंकि बच्चों को 4–4 कि0मी0 दूर स्कूल के लिए जाना पड़ता है।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
7	चुराह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएचसी कोहाल तथा बैरागढ़ खोलने की जो अधिसूचनाएं रदद की गई हैं उन्हें बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/सामान्य प्रशासन
8	क्षेत्र में बनी/ बनने वाली हाईड्रो परियोजनाओं से घराट समाप्त होते जा रहे हैं, परिवारों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इस बारे उचित कार्यवाही की जाए। साथ ही जिनकी भूमि परियोजनाओं में चली गई है उन्हें आउटसोर्स के आधार पर काम दिया जा रहा है उन्हें पक्की नौकरी प्रदान की जाए।	HPPCLtd./ HPSEBLtd.
9	साई कोठी–। तथा ।। के बिजली बोर्ड के कार्यालयों को उठवा दिया गया है इन्हें पुनः स्थापित किया जाए।	HPSEBLtd.
10	तीसा में सीएचसी 100 बिस्तर चलता है वहां डाक्टरों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
11	क्षेत्र में फैली हिमोफीलिया बीमारी के फैक्टर 4 तथा 8 के टीके अविलम्ब उपलब्ध करवाए जाएं।	स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा विभाग
12	शिमला–बैरागढ़ बस रूट चलती थी उसे बन्द किया गया है उसे पुनः चालू किया जाए।	HRTC/परिवहन विभाग
13	चांजू माता मन्दिर के लिए निजी बस रूट को extend किया जाए।	HRTC/परिवहन विभाग
14	चम्बा Remote Aspirational जिला है यहां 10 करोड़ रू0 की लागत से बस डिपो बना है इसका उदघाटन किया जाए।	HRTC/परिवहन विभाग
	2. डॉ0 जनक राज, भरमौर	
1	पीएचसी सुराल खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई थी उसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
2	सीएचसी भरमौर में एक ही एम्बुलैन्स है ऐसे दुर्गम/पहाड़ी/बर्फीले क्षेत्रों में एम्बुलैन्सों की संख्या (ड्राईवरों सहित) को बढ़ाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
3	निर्वाचन क्षेत्र में प्रशासनिक व शिक्षा क्षेत्र के रिक्त पड़े अधिकारियों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	शिक्षा/ समस्त सम्बन्धित विभाग
4	निर्वाचन क्षेत्र में कुछ समय के लिए जुलाई माह से लोक निमार्ण विभाग में सहायक अभियन्ता (SDO) पद के अधिकारी द्वारा अधिशाषी अभियन्ता (XEN) के कार्य किए जाते हैं इस पर पूर्णतः रोक लगाई जाए।	लोक निर्माण विभाग
5	जिला चम्बा में हाईड्रो परियोजनाओं से पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन होता है लेकिन पिछले तीन वर्षों से LADF की धनराशि लोगों को नहीं दी गई है इसे अविलम्ब प्रदान किया जाए।	HPPCLtd. / उपायुक्त चम्बा
6	जिला चम्बा में प्रति वर्ष आयोजित की होने वाली धार्मिक यात्रा (मणिमहेश यात्रा) के दायरे को बढ़ाया जाए। 30 अप्रैल के बाद आरम्भ होने वाली यह यात्रा राधाअष्टमी के 5 दिन बाद तक चलती है इसे अधिकारिक तौर पर और आगे बढ़ाया जाए। साथ ही दो–तीन स्थानों पर हैल्थ कैम्प, बचाव कैम्प इत्यादि का निर्माण भी सरकार / प्रशासन द्वारा किया जाए।	भाषा कला संस्कृति / उपायुक्त चम्बा

7	भरमौर में Wool Federation का कार्यालय खोला जाए या पालमपुर वाले कार्यलय को भरमौर में स्थानांतरित किया जाए।	
8	मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थाई प्रबन्ध किया जाता है इसे प्रशासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से स्थाई तौर पर निर्मित किया जाए जैसे Toilets, Sheds, Health and Rescue Camps इत्यादि।	भाषा कला संस्कृति / उपायुक्त चम्बा
9	क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए मनरेगा के अन्तर्गत पंचायतों द्वारा Rain Water Harvesting Structure/ Tanks का निर्माण किया जाए साथ ही गाँव के एक मुहाने से भीतर तक Fire Hydrand System install किया जाए। पायलट आधार पर भरमौर व चौरासी मन्दिर के क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
10	भरमौर क्षेत्र में पंचायतों के माध्यम से रिक्त पड़ी सरकारी भूमि / निजी भूमि पर अखरोट, चिलगोजा, ठांगी इत्यादि फलदार पेड़–पौधों को लगाया जाए।	वन/ उद्यान विभाग
11	निर्वाचन क्षेत्र के गैहरा–धरवाल में आदर्श अस्पताल का निर्माण किया जाए।	स्वास्थ्य / चिकित्सा शिक्षा विभाग
12	पांगी में चाईल्ड, गाईनी, आर्थो तथा मेडिसीन के स्पैर्सलिस्ट डॉक्टरों का प्रबन्ध प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
13	धरवाला तथा गैहरा के बीच कहीं पर भी एक पुलिस थाना खोला जाए।	पुलिस विभाग
14	VKVNY की धनराशि का 10 प्रतिशत विधायक गृह निर्माण में प्रदान कर सकें इस बारे उचित कार्यवाही की जाए।	योजना विभाग
	3. श्री नीरज नैयर, चम्बा	
1	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
2	चम्बा–चुवाड़ी जोत टनल का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3	चम्बा शहर में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए पुराने बस अडडे के स्थान पर मल्टीपर्पज भवन का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास/ परिवहन विभाग/ उपायुक्त चम्बा
4	धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से मणिमहेश यात्रा की समयावधि को बढ़ाया जाए।	भाषा कला एवं संस्कृति विभाग/ उपायुक्त चम्बा
5	हैलीपोर्ट का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए।	पर्यटन/शहरी विकास विभाग
6	चम्बा हैलीपैड से मणिमहेश यात्रा के हैलीकॉप्टर की सुविधा चलाई जाए।	पर्यटन/शहरी विकास विभाग
7	चम्बा इन्डोर स्टेडियम के लिए 2.5 करोड़ रू0 केन्द्र के पास से लोक निर्माण विभाग को आए हैं। प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	युवा खेल सेवाएं/ लोक निर्माण विभाग
8	पर्यटन की दृष्टि से तलेरू डैम में रिवर रॉफटिंग, बोटिंग, जैट स्ट्रीम, मोटर स्ट्रीम इत्यादि की जलक्रीड़ा की गतिविधियां चलाई जाएं।	युवा खेल सेवाएं/ पर्वतारोहण खेल संस्थान
9	खजियार में पैरा ग्लाईडिंग, अन्य खेल व साहसिक गतिविधियों को चलाया जाए जिससे स्थानीय युवाओं को रोजागार प्राप्त होगा।	युवा खेल सेवाएं/ पर्वतारोहण खेल संस्थान
10	चम्बा शहर से चम्बा नये बसे अडडे तक रोपवे बनने की डी.पी. आर. लगभग 29 करोड़ रू0 को स्वीकृत कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	RTDC (Ropeways)
11	चम्बा तथा पठानकोट बस डिपो के स्टाफ का rationalization किया जाए ताकि क्षेत्र में ड्राईवरों व कन्डक्टरों की कमी को दूर किया जा सके।	HRTC/ परिवहन विभाग
12	चम्बा टाउन के लिए रू0 480 करोड़ की डीपीआर को केन्द्र/ एडीबी/ अन्य माध्यम से 90:10 या 80:20 में स्वीकृत करवाकर विकास कार्य आरम्भ किए जाएं।	शहरी विकास विभाग

13	निर्वाचन क्षेत्र की जो पंचायतें चम्बा, मैहला, तीसा ब्लॉक में पड़ती हैं उन्हें भरमौर या मैहला में किया जाए।	ग्रामीण विकास/ पंचायती राज विभाग
14	वैल्फेयर के अन्तर्गत जो पैसे मकान बनाने के लिए आते हैं उनमें सबसे ज्यादा एस.सी जाति के लिए आते हैं जबकि एस.टी व ओ. बी.सी जाति के लिए इसमें न के बराबर आते हैं। इस बारे उचित कार्यवाही की जाए ताकि सभी को मकान मिल सके।	सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता/ SOMA Deptt.
4. श्री डी. एस. ठाकुर, डलहौजी		
1	डलहौजी का क्षेत्र बाहरी राज्यों की सीमा से लगा क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में बढ़ रहे नशे/ चिटटे पर पूर्ण रोक लगाई जाए।	पुलिस विभाग
2	निर्वाचन क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में डाक्टरों के रिक्त पदों का प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
3	आदर्श अस्पताल सलूणी में पूरी मूलभूत सुविधाएं पूरे स्टाफ, पूरे डॉक्टर्ज़ तथा सभी आवश्यक उपकरणों के साथ प्रदान की जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
4	सिवील अस्पताल डलहौजी में डॉक्टरज़ तो हैं पर वहां आपॅरेशन करने के व अन्य उपकरण उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण मरीजों को रैफर करना पड़ता है। अतः यहां पर पूरे उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
5	स्वास्थ्य संस्थान तेलका में भी डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
6	जल शक्ति विभाग का डिवीजन डलहौजी बन्द न हो इस बारे जस्टीफिकेशन बनाकर विभाग उचित कार्यवाही करे।	जल शक्ति विभाग
7	क्षेत्र की पीने की योजनाओं में पाईपों की मुरम्मत व डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उचित बजट का प्रावधान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8	कोरोना काल में बन्द की गई बसों को पुनः चलाया जाए। साथ ही सलूणी से टांडा के लिए एक नई बस सेवा भी चलाई जाए।	HRTC/परिवहन विभाग
9	बाथरी–लंघेरा सड़क के विस्तारीकरण / सुदृढ़ीकरण/ चौड़ा करने की डी.पी.आर. शीघ्र बनाकर इसका कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
10	डलहौजी में 3 पार्किंग क्षेत्रों का निर्माण किया जाए जिसमें Toilets की भी सुविधा प्रदान हो।	शहरी विकास विभाग
11	डलहौजी में बस अडडे का निर्माण किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
12	33 केवी स्टेशन/सब–स्टेशन बनीखेत तथा तेलका का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए।	HPSEBLtd./HPTCLtd.
13	क्षेत्र के व्यापारियों तथा ठेकेदारों द्वारा पिछले 10 वर्षों का आयकर(GST) नहीं भरा गया था अब उन्हें पैनल्टी पड़ रही है उन्हें राहत प्रदान की जाए।	आयकर/उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग (Excise & Taxation)
14	VKVNY की धनराशि का 10 प्रतिशत विधायक गृह निर्माण में प्रदान कर सकें इस बारे उचित कार्यवाही की जाए।	योजना विभाग
15	एफ.सी.ए. के कारण पिछले 5–7 वर्षों से कुछ सड़कें नहीं बन पा रही हैं इन एफ.सी.ए. मामलों का तीव्रगति से निपटाया जाए।	वन विभाग/ उपायुक्त चम्बा
16	पीएचसी करवाल को खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई है इसे बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग/ सामान्य प्रशासन
17	बीडीओ कार्यालय बाथरी को खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई है उसे बहाल किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
18	पधरी जोत में सलूणी तहसील के अन्तर्गत लगभग 17 हजार बीघा भूमि जम्मू कश्मीर में है इसे वापिस हिमाचल में लाया जाए।	राजस्व विभाग/ उपायुक्त/
19	साथ ही जो पुलिस चौकियां सीमा पर थी उन्हें कुछ नीचे शिफ्ट किया गया था उन्हें पुनः उसी सीमा वाले स्थान पर स्थापित किया जाए ताकि घुसपैठ व कब्जे की समस्या का हल हो सके।	पुलिस विभाग
20	चम्बा जिले में एसपीओज़ के लगभग 500 परिवार हैं अतः इनके मानदेय को बढ़ाया जाए।	पुलिस विभाग

6. जिला बिलासपुर		
1. श्री जीत राम कटवाल, झण्डूता		
1	री रंडोह गाँव के लिए सड़क के कार्य को पूर्ण करने के लिए उचित बजट प्रदान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2	री रंडोह पुल बनकर तैयार है इसकी एपरोचिज़ के कार्य को धन उपलब्ध करवाकर शीघ्र पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3	मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना की धनराशि को जारी किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4	टप्पे, दभोग, माण्डवा पुलों के निर्माण/एपरोचिज़ के कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
5	ससौटा से खैण्डल सड़क पुल सहित की डी.पी.आर. को शीघ्र तैयार कर स्वीकृत करवाया जाए और निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6	सीएचसी तलाई तथा सिवील अस्पताल बरठीं के निर्माणाधीन भवनों के लिए बजट की उचित व्यवस्था की जाए और कार्यो को पूरा किया जाए। साथ ही क्षेत्र में एम्बलैन्सों की कमी को भी दूर किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
7	बागछ्ल पुल के एपरोचिज़ के कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
8	क्षेत्र की पीएचसीज़ तथा सीएचसीज़ में स्पैसलिस्ट डॉक्टरों एमडी, (आर्थो एवं गाईनी) इत्यादि के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
9	विद्युत विभाग का डिवीजन झण्डूता में खोला जाए।	HPSEBLtd.
10	लो वोल्टेज की समस्या का हल किया जाए।	HPSEBLtd.
11	निर्वाचन क्षेत्र के लिए 132 के.वी. सब–स्टेशन के लिए 15–18 बीघा भूमि सुन्हाणी में उपलब्ध है शीघ्र इसके कार्य को आरम्भ/पूरा किया जाए।	HPPTCLtd.
12	पर्यटन की दृष्टि से सरकार द्वारा गोविन्दसागर झील में जलक्रीड़ा की गतिविधियों का पॉलीसी बनाकर एक चरणबद्ध तरीके से सुचारू संचालन किया जाए।	युवा खेल सेवाएं/ पर्वतारोहण खेल संस्थान
13	जल शक्ति विभाग में पुरानी पाईपों तथा मशीनरी को बदला जाए। साथ ही पेयजल योजनाओं में वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटस का निर्माण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
14	एफसीए के मामले में उपायुक्त द्वारा ली जाने वाली बैठक में डीपीआर की प्रगति/रिपोर्ट को भी माननीय विधायकों के साथ सांझा किया जाए ताकि आ रही बाधाओं का तुरन्त समाधान हो सके। इन बैठकों में अधीक्षण अभियन्ता(सम्बन्धित विभाग), कन्जरवेटर (वन) को भी शामिल किया जाए और माननीय विधायकों को भी बैठकों में आमन्त्रित किया जाए।	उपायुक्त बिलासपुर
15	वैल्फेयर विभाग में घर बनाने के लिए किसी पात्र व्यक्ति को पहली किश्त दी गई और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों को दूसरी किश्त नहीं मिल पाई है जिससे काम अधूरे पड़े हैं। क्षेत्र के इन 5–6 मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि इन गरीब लोगों की इस समस्या को हल किया जा सके।	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
16	सीर खडड पर डैम बनाने की डी.पी.आर. को शीघ्र केन्द्र से स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए। साथ ही सम्बन्धित विधायक से भी सम्पर्क कर समस्या व प्रगति की जानकारी सांझा की जानी चाहिए।	जल शक्ति विभाग
17	गुग्गा गेहड़वीं के पास छमाण नामक स्थान पर सुरंग का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
18	ज्योरिपतन–स्वारघाट रोपवे का निर्माण किया जाए।	RTDC
19	निर्वाचन क्षेत्र में डिनाटीफाई किए गए संस्थानों को पुनः बहाल किया जाए।	समस्त सम्बन्धित विभाग

20	प्रदेश के गरीब भूमिहीन परिवारों ने सरकारी 2–3 बिस्वा भूमि पर मकान बनाएं है उनके घरों के नीचे 5–6 मीटर सरकारी भूमि आ गई है। इन्हे नियमित करने के लिए कमेटी का निर्माण किया जाए तथा शीघ्र इनकी समस्याओं का निपटारा किया जाए।	वन / राजस्व विभाग
	2. श्री त्रिलोक जम्वाल, बिलासपुर	
1	बिलासपुर जिला में 1400 करोड़ रू0 के प्रोजेक्ट (गोविन्दसागर झील में डूबे प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्वार) को शीघ्र स्वीकृत कर कार्य आरम्भ किया जाए।	पर्यटन/ भाषा कला एवं संस्कृति/ग्रामीण विकास विभाग
2	बझवाणी पुल के लिए लोगों की भूमि का अधिग्रहण कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3	नौणी–शिमला फोरलेन के कार्य को आरम्भ/पूरा किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4	भानुपली–बिलासपुर रेल लाईन में बिलासपुर से बरमाणा तक की भूमि को शीघ्र अधिग्रहित कर उचित मुआवजा लोगों को प्रदान किया जाए।	परिहवन विभाग (रेलवे)
5	गोविन्दसागर रिजरवायर में लूहणु मैदान के आर–पार एक बड़ा प्रोजेक्ट जैसे रिवर बैंक, सोलर हब इत्यादि का निर्माण किया जाए।	पर्यटन/लोक निर्माण/ उपायुक्त बिलासपुर
6	कोलडैम रिजरवायर में स्पोर्टज़ एक्टीविटी (जलक्रीड़ाएं) चलाई जाएं।	युवा खेल सेवाएं/ पर्वतारोहण खेल संस्थान/पर्यटन विभाग
7	कोलडैम से पानी की एक बड़ी योजना 15–16 पंचायतों के लिए बनी है लेकिन कन्दरौर पुल के पास एक पाईप की सप्लाई को दो पाईपों में डाइवर्ट किया गया है जिससे दबाब कम हो जाता है और पूरा पानी पंचायतों तक नहीं पहुंच पा रहा है इस बारे विभाग उचित कार्यवाही करे।	जल शक्ति विभाग
8	निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर के छोटे–छोटे कस्बों में लो वोल्टेज की समस्या, सड़क के साथ दुकानों तथा साथ लगते एरिया में बिजली की तारों के स्थान पर ओवरहैड केबल का प्रयोग किया जाए।	HPSEBLtd.
9	बिजली की तारों को ओवरहैड या अंडरग्राउंड करने के लिए विधायक निधि से विद्युत विभाग को धन देने बारे विभाग कार्यवाही करे।	योजना विभाग
10	मुख्यमंत्री लोक भवन कुठेड़ा तथा कन्दरौर का निर्माण कार्य लगभग 80–90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है। शेष धनराशि जारी कर निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
11	निर्वाचन क्षेत्र बिलासपुर में रविवार के दिन भी बसों को चलाया जाए ताकि स्थानीय लोगों को आने–जाने में कोई बाधा न हो।	HRTC
12	नशे पर पूर्ण रोक लगाने के लिए प्रदेश के स्कूलों तथा पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं। साथ ही सरकारी अस्पताल में 4–6 कमरे इन चिट्टे व नशे से प्रभावित लोगों/बच्चों के लिए आरक्षित किए जाएं ताकि इनका ईलाज हो सके।	स्वास्थ्य/ समस्त शैक्षणिक विभाग (All Educational Deptts.)
13	नशे के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाई जाए तथा जिन लोगों के खिलाफ नशे के केस चले हैं उन लोगों को सार्वजनिक मंच/ स्थानों से दूर रखा जाए।	पुलिस / समस्त सम्बन्धित विभाग
14	विधायक निधि से दी गई धनराशि पंचायतों में समय पर खर्च नहीं की जाती है इस बारे भी विभाग उचित कार्यवाही करे।	योजना विभाग
15	निर्वाचन क्षेत्र में संस्थानों को खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई हैं उन्हें बहाल किया जाए।	समस्त सम्बन्धित विभाग
16	पीएचसी बरमाणा को बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
17	उप–तहसील हरलोग को भी बहाल किया जाए।	राजस्व विभाग
18	जल शक्ति विभाग के सब–डिवीजन कुठेड़ा को भी बहाल किया जाए।	जल शक्ति विभाग
19	वन विभाग के अन्तर्गत जंगलों में 10–10 कि0मी0 के क्षेत्र में बाड़ लगाई जाए ताकि वहां इन प्रदेश के बेसहारा पशुओं को भोजन व पानी के साथ आश्रय प्रदान किया जा सके।	वन/पशु पालन विभाग

3. श्री रणधीर शर्मा, श्री नैना देवी जी		
1	विधायक निधि को बढ़ाया जाए तथा नियमित रूप से जारी भी किया जाए।	योजना विभाग
2	विधायक प्राथमिकता योजनाओं की डी.पी.आरज़ का सर्वे समयबद्ध तरीके से किया जाए ओर निश्चित समयावधि में तैयार किया जाए।	लोक निर्माण/ जल शक्ति/ परिवहन विभाग
3	स्वाहन से कटिरड़–पगवाना सड़क की डी.पी.आर. जुलाई 2021 को नाबार्ड को गई है जो स्वीकृति हेतु विचाराधीन है। इसे अतिशीघ्र स्वीकृत किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4	एफसीए के मामलों में एक बार ही ऑब्जेक्शन लगना चाहिए और इन एफसीए के लम्बित मामलों को अविलम्ब प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।	वन विभाग
5	क्षेत्र के तीन स्कूलों बस्सी, स्वारघाट तथा जगातखाना में साईंस ब्लॉक का निर्माण किया गया है। ठेकेदारों को बिना देरी के धनराशि जारी की जाए।	शिक्षा/ लोक निर्माण विभाग
6	नवगॉंव–बैरी–बरमाणा सड़क को सीआरएफ, इन्डसट्रीयल कारिडोर या अन्य माध्यम से धनराशि उपलब्ध करवाकर डबल लेन किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7	अली खडड से 24 पेयजल व 7 सिंचाई स्कीमें चलती हैं। इस खडड से अर्की विधानसभा के लिए एक नई योजना बन रही है इसे रोक कर अर्की के लिए कोलडैम से पानी उठाकर योजना का निर्माण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8	जल शक्ति विभाग के डिवीजन को बहाल किया जाए। साथ ही निर्वाचन क्षेत्र में विभाग के अधीन फील्ड स्टाफ व अन्य तकनीकी स्टाफ की कमी को दूर किया जाए और सब–डिवीजन स्तर पर कम से कम एक जेई का होना सुनिश्चित किया जाए।	जल शक्ति विभाग
9	विद्युत विभाग में भी टीमेट, लाईनमैन, जे.ई., फील्ड स्टाफ व अन्य तकनीकी स्टाफ के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	HPSEBLtd.
10	निर्वाचन क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों व अन्य तकनीकी स्टाफ के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। साथ ही आदर्श अस्पताल श्री नैनादेवी जी में 6 चिकित्सक थे अब एक ही है। अतः इनकी कमी को पूरा कया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
11	प्राथमिक विद्यालय बाग–चंगयाणा में 5–6 बच्चे पढ़ते हैं। यह स्कूल एक महीने से बन्द है इसे बहाल किया जाए।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
12	फोरलेन बनने से क्षेत्र की 8–10 पंचायतों के लोगों को बसों की कमी का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र की जनता के लिए बसों की सुविधाएं बस रूट सहित प्रदान की जाएं।	परिवहन विभाग/ HRTC
13	नए क्षेत्र नंदबैला को भी औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए।	उद्योग विभाग
14	4–5 पटवार सर्कल क्षेत्र में खोले गये थे। इनमें पटवारियों को तीन दिन यहां, तीन दिन दूसरी पंचायत में बिठाकर ही कार्य चलाया जाए जब तक की नई पटवारी की भर्ती सम्पन्न नहीं होती है।	राजस्व विभाग
15	33 के.वी. सब स्टेशन नैनादेवी जी के कार्य को तीव्रगति से पूरा किया जाए।	HPSEBLtd./ HPPTCLtd.
16	डिग्री कॉलेज स्वारघाट शीघ्र आरम्भ किया जाए।	शिक्षा विभाग
7. जिला लाहौल–स्पिती		
1. श्री रवि ठाकुर, लाहौल–स्पिती		
1	लाहौल स्पिती के लिए जल शक्ति तथा लोक निर्माण की योजनाओं में बजट की पूरी व्यवस्था की जाए।	लोक निर्माण/ जल शक्ति/ जनजातीय विकास विभाग

2	मुदभावा सड़क तथा लियो बाई पास सड़क का निर्माण/सुधार/ विस्तार/सुदृढ़ीकरण किया जाए।	लोक निर्माण / जनजातीय विकास विभाग
3	लिंक रोड़ की–गोम्पा से लापचे, तिंदी से दराटी लिंक रोड़, सिसु चन्द्रा नर्सरी पुल, जुबरंग–राशल–कुगती रोड़ का निर्माण किया जाए।	लोक निर्माण / जनजातीय विकास विभाग
4	बहाव सिंचाई योजना खांडिप, तांदी, सुमनम, लापशक, इत्यादि 16 गाँवों के लिए योजना, बहाव सिंचाई योजना जूलिंग–सिंधवाड़ी तथा उठाऊ सिंचाई योजना जालमा–फुरा का निर्माण/ विस्तारीकरण किया जाए।	जल शक्ति/ जनजातीय विकास विभाग
5	बढ़ते पर्यटन की दृष्टि से सीवरेज योजना केलांग, उदयपुर तथा काजा का निर्माण किया जाए।	जल शक्ति/ जनजातीय विकास विभाग
6	मुद–फारका पुल, ज्वालिंग–थिरोट पुल, शुशना पुल का निर्माण /सुधार किया जाए।	लोक निर्माण / जनजातीय विकास विभाग
	खांगसर उठाऊ सिंचाई योजना का निर्माण किया जाए।	जल शक्ति/ जनजातीय विकास विभाग
8. जिला कांगड़ा		
1. श्री रणधीर सिंह निक्का, नूरपुर		
1	लिंक सड़क बढ़वाल–टिक्कर–नगरोटा–कोट पलाड़ी–चौकी लदोड़ी–ठाणा –पन्दरेड़–इन्दौरा घराट रोड़ का सुधारीकरण व चौड़ीकरण /विस्तारीकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2	नागाबाड़ी से बदूही–खनी झिकली–खनी उपरली–औंद–सिम्बली सड़क का सुधारीकरण व चौड़ीकरण /विस्तारीकरण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
3	SCDP के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 की प्राथमिकताओं में पक्का टाला रेलवे फाटक से गुरु रविदास मन्दिर सड़क और खलून हरिजन बस्ती सम्पर्क सड़क का निर्माण किया जाए।	SOMA/ लोक निर्माण विभाग
4	SCDP के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 की प्राथमिकताओं में 75 प्रतिशत तक पूर्ण कार्यों में सम्पर्क सड़क हरिजन बस्ती मैकड़ तथा परगना से गरसाड़ा सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए।	SOMA/ लोक निर्माण विभाग
5	SCDP के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 की प्राथमिकताओं में प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण किया जाए जो फोरलेन की चपेट में आ गया है।	SOMA/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
6	SCDP के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 की प्राथमिकताओं में उप–स्वास्थ्य केन्द्र खुखेड़ के भवन का निर्माण किया जाए।	SOMA/स्वास्थ्य विभाग
7	SCDP के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 की प्राथमिकताओं में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनपुर के भवन का निर्माण किया जाए।	SOMA/आयुर्वेदा विभाग
8	SCDP के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 की प्राथमिकताओं में सब–तहसील सदवां जो किराये के भवन में चल रही है के लिए नया भवन निर्माण किया जाए।	SOMA/राजस्व विभाग
9	भूमि कटाव को रोकने के लिए चक्की और जबर खडड पर बांधों का निर्माण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
10	घरेली खडड के साथ लगती पंचायतों कोलान, भुनाड़ सिम्बली पैल, टूंड, बाशा–बजीरा, जाश, थली, जसूर इत्यादि में भूमि कटाव के बचाव हेतु इस खडड का तटीयकरण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
11	प्रदेश में बढ़ते नशे (चिट्टा) पर पूर्ण रोक लगाई जाए।	पुलिस विभाग
12	नूरपुर क्षेत्र में बढ़ते हेपाटाईटस सी, बी तथा एचआईवी के मामलों को गम्भीरता से लेकर इनकी रोकथाम की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
	नूरपुर में मेडिकल कॉलेज खोला जाए जिससे साथ लगते 5 निर्वाचन क्षेत्रों की जनता को इसका लाभ प्राप्त होगा।	चिकित्सा शिक्षा विभाग

13	रा0व0मा0 पाठशालाएं कण्डवाल तथा भड़वार के भवन जो फोरलेन में चपेट में आए हैं के लिए स्थानीय लोगों द्वारा भूमि भी उपलब्ध करवा दी गई है शीघ्र इनका निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	शिक्षा विभाग
14	मातृ शिशु अस्पताल नूरपुर में बिजली–पानी की उचित व्यवस्था कर इसे चालू किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिल सके।	स्वास्थ्य विभाग
15	एसई कार्यालय को पुनः नूरपुर में खोला जाए।	HPSEBLtd.
16	ब्रान्डा में डिग्री कॉलेज खोला जाए।	शिक्षा विभाग(उच्च)
17	नूरपुर के वार्ड नं0 9 खजियां तथा भरियारा में कुछ लोगों के घर Land Slide में प्रभावित हुए हैं। अतः इन्हें नई जगह पर घर बनाने के लिए भूमि प्रदान करने के लम्बित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।	राजस्व विभाग
18	साईंस लैब खन्नी में बन रही है जिसके लिए 40 लाख रू0 की धनराशि उपलब्ध करवाकर निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग
19	नूरपुर कॉलेज के बन रहे नये भवन के लिए 5 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाकर निर्माण कार्य को पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग
20	खनन के सम्बन्ध में नई नीति का निर्माण किया जाए जिसमें खनन क्षमता (Mining capacity), Mechanical permission को बढ़ाने बारे भी ध्यान रखा जाए। साथ ही सरकार 4–5 कलस्टरों के रूप में Mining Plan तैयार करे, सरकार अपने आप 3–4 महीनों में EC करवाए, पांचवें या छठे महीने में Bid करवाए, जिससे अगले दिन से ही सरकार को राजस्व प्राप्त होना आरम्भ हो जाएगा।	उद्योग विभाग
2. श्री मलेन्द्र राजन, ईन्दौरा		
1	सिवील अस्पताल गंगथ तथा इन्दौरा में आर्थो और मेडिसिन के डॉक्टरों की भी नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाए। साथ ही इन अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की नई मशीनें भी उपलब्ध करवाई जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
2	नूरपुर क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज या जोनल अस्पताल का निर्माण किया जाए।	चिकित्सा शिक्षा/ स्वास्थ्य विभाग
3	क्षेत्र में विद्यमान रामगोपाल मन्दिर के साथ मन्दिर के नाम से सैंकड़ों है0 भूमि विरान पड़ी है जिस पर लोगों के अवैध कब्जे हैं। इन अवैध कब्जों को हटाकर इस भूमि का उपयोग मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए किया जाए।	चिकित्सा शिक्षा/ स्वास्थ्य/ भाषा कला एवं संस्कृति/ राजस्व/ विभाग
4	गंगथ तथा बसन्तपुर के रा0व0मा0 पाठशालाओं को School of Excellence में शामिल किया जाए।	शिक्षा विभाग
5	क्षेत्र की रा0व0मा0 पाठशालाओं ईन्दौरा, गंगथ, भोगरवां, गगवाल, मोडली, डागला इत्यादि का सुदृढ़िकरण किया जाए। इन स्कूलों में हर प्रकार की सुविधा जैसे साईंस लैब, विज्ञान और कॉमर्स संकाय की कक्षाएं आरम्भ करना, स्वच्छ जल, शौचालय, खेल मैदान, पूर्ण अध्यापक/प्रवक्ता, निजी स्कूलों की भान्ति उचित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इत्यादि प्रदान की जाए।	शिक्षा विभाग
6	राजीव गॉंधी डे बोर्डिंग स्केल मोगी में खोला जाए।	शिक्षा विभाग
7	क्षेत्र में सरकारी प्राथमिक व वरिष्ठ विद्यालयों की कुल संख्या 10–11 है तथा 15 निजी क्षेत्र के स्कूल हैं। इन सरकारी विद्यालयों में कुछ विद्यालय बॉयज तथा गर्लज़ के अलग–2 हैं। इन स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया जाए जो इन निजी स्कूलों के अध्यापकों को सरकारी स्कूलों में सेवाएं देने के लिए चयन करे।	शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
8	शिक्षा विभाग के पास भेजी गई ईन्डोर स्टेडियम–कम–ऑडिटोरियम की प्रस्तावना को शीघ्र स्वीकृत कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	शिक्षा विभाग

9	प्रदेश के सभी स्कूलों में सप्ताह में एक बार अध्यात्मिक कक्षाओं का चलन आरम्भ किया जाए।	शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
10	आई.टी.आई गंगथ में और ट्रेड चलाए जाएं।	तकनीकी शिक्षा
11	शिक्षा विभाग के नाम लगभग 100 कनाल की उपलब्ध भूमि पर पॉलटेकनिक कॉलेज खोला जाए।	शिक्षा/ तकनीकी शिक्षा विभाग
12	अवैध खनन तथा नशे की बढ़ती गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस थाना इन्दौरा, पुलिस चौकी ठाकुरद्वारा तथा ढंगुपुर में वाहनों की कमी तथा स्टाफ की कमी को दूर किया जाए।	पुलिस विभाग
13	भदरवाह में Permanent Police Post खोली जाए।	पुलिस विभाग
14	अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ट्रैक्टरों को व्यवसायिक वाहनों (Commercial Vehicle) की श्रेणी में शामिल किया जाए।	परिवहन विभाग
15	प्रदेश में बढ़ते नशे (चिट्टा) पर पूर्ण रोक लगाने के लिए पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति को पकड़ाई गई मात्रा के हिसाब से ईनाम प्रदान किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग सूचना प्रदान कर सकें। साथ ही इन सूचित करने वाले व्यक्तियों का नाम गुप्त रखा जाए।	पुलिस विभाग
16	Drug Control App की अधिक से अधिक Publicity की जाए।	पुलिस विभाग
17	अवैध खनन तथा चिट्टे के नशे को रोकने के लिए राज्य स्तर पर एक कमेटी का निर्माण कर गॉंव–गॉंव तक जागरूकता अभियान चलाया जाए	उद्योग/पुलिस/पंचायती राज/ ग्रामीण विकास/ सम्बन्धित विभाग
18	प्रदेश की स्वंय सेवी संस्थाओं तथा महिला मण्डलों द्वारा जो उत्पाद (Products) तैयार किए जाते हैं उन्हें ऑनलाईन मार्केटिंग की सुविधा प्रदान की जाए। उनके लिए कोई मोबाईल ऐप का निर्माण किया जाए और हिम ईरा की दुकानों में इनके लिए सामान विक्रय करने हेतु प्रबन्ध किया जाए।	ग्रामीण विकास /पंचायती राज/उद्योग/ महिला बाल विकास/ सम्बन्धित विभाग
19	डमटाल मन्दिर के साथ मन्दिर की खाली पड़ी भूमि पर शॉपिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण किया जाए।	भाषा कला एवं संस्कृति विभाग/ उपायुक्त
20	प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो वर्दी, बैग व अन्य चीजें सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं उन सभी का निर्माण इन स्वंय सेवी संस्थाओं तथा महिला मण्डलों द्वारा करवाया जाए जिससे इन्हें स्थायी रोजगार भी प्रदान किया जा सकेगा।	शिक्षा/ग्रामीण विकास /पंचायती राज//उद्योग महिला बाल विकास/ सम्बन्धित विभाग
21	सभी माननीय विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थायी कार्यालय व स्टाफ की सुविधा प्रदान की जाए।	सामान्य प्रशासन
22	प्रदेश के गरीब लोगों को भवन निर्माण की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विधायक क्षेत्र विकास निधि में भवन निर्माण हेतु धनराशि देने का प्रावधान किया जाए।	योजना विभाग
23	निर्वाचन क्षेत्र के कन्दोड़ी में HPMC की भूमि पर Honey Processing Unit चलाई जा रही थी। यहॉं पर अब CA Store या सब्जी मण्डी का निर्माण किया जाए।	उद्यान/कृषि/Agriculture Marketing Board/ HPMC
24	भदरोहा में प्रस्तावित ईको पॉर्क का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	वन विभाग
25	विद्युत विभाग में फिल्ड स्टाफ की कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।	HPSEBLtd.
26	क्षेत्र के मिनवा नामक स्थान पर NH के साथ बहुत सी भूमि खाली पड़ी है यहां पर नया औद्योकिग क्षेत्र स्थापित/विकसित किया जाए।	उद्योग विभाग
27	शाहनहर परियोजना के 31 ट्यूब्वैल बिजली काटने की वजह से बन्द पड़े हैं इन्हें अतिशीघ्र चालू किया जाए।	जल शक्ति विभाग/ HPSEBLtd.
28	शाहनहर परियोजना में अधिकतर क्षेत्र ईन्दौरा तथा फतेहपुर निर्वाचन क्षेत्र का पड़ता है इसलिए इसका डिवीजन बडुखर में स्थानांतरित किया जाए।	जल शक्ति विभाग

29	डमटाल मन्दिर की भूमि पर लगभग 9 क्रशर चल रहे हैं। यहां पर अवैध खनन हो रहा है इसे रोका जाए। साथ ही यहां की भूमि को खनन के लिए ऑक्शन किया जाए जिससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।	उद्योग विभाग/State Geologist (Geological Wing)
3. श्री भवानी सिंह पठानिया, फतेहपुर		
1	री कॉलेज के निर्माणाधीन दो भवनों में पहले एक भवन के कार्य को पूर्ण कर कक्षाएं आरम्भ की जाएं तथा उसके बाद दूसरे निर्माणाधीन भवन के कार्य को पूर्ण किया जाए। इनके कार्यो को पूर्ण करने के लिए उचित बजट की व्यवस्था की जाए।	शिक्षा विभाग
2	कम्बाईन्ड ऑफिस भवन फतेहपुर के भी निर्माणाधीन भवन के कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए।	राजस्व विभाग
3	क्षेत्र के आदर्श अस्पताल में सभी डॉक्टरों व अन्य तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसी भी स्थान से क्षेत्र में नियुक्त होने वाले डॉक्टरों को नियुक्त करने से पहले विभाग उनकी सहमति जरूर ले।	स्वास्थ्य विभाग
4	रोजगार तथा पर्यटन की दृष्टि से पौंग डैम के क्षेत्र को विकसित करने के लिए सबसे पहले क्षेत्र में सड़कों (कतराह, ललवाणा, सियोली आदि) तथा विद्युत व्यवस्था (33 केवी सब–स्टेशन निर्माण) को दुरूस्त किया जाए।	पर्यटन/लोक निर्माण/ HPSEBLtd.
5	रोजगार तथा पर्यटन की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्र को चार हिस्सों के विभाजित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए जैसेः पर्यटन की दृष्टि से पौंग डैम बैल्ट, औद्योगिक दृष्टि से रियाली बैल्ट, शहरीकरण की दृष्टि से रैन बैल्ट प्रशासनिक दृष्टि से फतेहपुर बैल्ट ।	पर्यटन/उद्योग/शहरी विकास विभाग
6	निर्वाचन क्षेत्र में फसलों, फल तथा सब्जी उत्पादन की बहुलता के दृष्टिगत 52 पंचायतों के लिए सिंचाई की निर्बाध व सुचारू व्यवस्था प्रदान की जाए।	जल शक्ति/उद्यान/कृषि विभाग
7	रोजगार की दृष्टि से स्थानीय लोगों/युवाओं को राजीव गॉंधी स्टार्टअप योजना के तहत प्रशिक्षित कर उन्हें उपदान(subsidy) प्रदान कर House Boats, Solar Boats, Motor Boats, etc. की व्यवस्था कर रोजगार प्रदान किया जाए।	युवा खेल सेवाएं/ पर्वतारोहण खेल संस्थान
8	निर्वाचन क्षेत्र के जखबड़ नामक स्थान पर 200–200 कनाल के 2 रकवे हैं यहॉं पर औद्योगिक क्षेत्र शीघ्र विकसित किया जाए ताकि 2–3 साल में यहां पहला उद्योग/फैक्ट्री स्थापित की जा सके।	उद्योग विभाग
9	शहरीकरण की ओर कदम बढ़ाते हुए राजा का तालाब तथा फतेहपुर में सीवरेज की उचित व्यवस्था प्रदान की जाए।	शहरी विकास/ जल शक्ति विभाग
10	विद्युत विभाग में खम्बों, तारों व अन्य उपकरणों की कमी को दूर कर विद्युत व्यवस्था का निर्बाध सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सर्कल कार्यालय डलहौजी को फतेहपुर में स्थानांतरित किया जाए जिसके लिए E-in-C शाहनहर का रिक्त कार्यालय भवन उपलब्ध है।	HPSEBLtd. / जल शक्ति
11	बस अडडा फतेहपुर का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
12	राजीव गॉंधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण आरम्भ किया जाए।	शिक्षा विभाग
13	रैण पुलिस चौकी को थाना बना दिया गया है जब तक इसका नया भवन निर्मित नहीं होता तब तक इसके साथ लगते पुराने अस्पताल के भवन से ही इसका संचालन किया जाए जिसके लिए प्रस्तावना भी विभाग द्वारा भेजी जा चुकी है।	पुलिस/ स्वास्थ्य विभाग
14	मेडिकल कॉलेज या जोनल अस्पताल राजा का तालाब में खोला जाए।	स्वास्थ्य/ चिकित्सा शिक्षा विभाग
15	नूरपुर अस्पताल को जोनल अस्पताल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
16	शाहनहर सिंचाई परियोजना की मुरम्मत एवं रख–रखाव के लिए बजट की उचित व्यवस्था की जाए। साथ ही सिंचाई योजनाओं की बिजली काटने से पहले उच्चाधिकारियों से अनुमति ली जाए या	HPSEBLtd. / जल शक्ति

	मुख्य सचिव या सरकार स्तर पर किसी High Power Committee का निर्माण किया जाए।	
17	कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्र के पास PMKSY के तहत लम्बित 86-86 करोड़ रुपये की दो डीपीआरज़ को शीघ्र स्वीकृत करवाया जाए।	जल शक्ति विभाग
18	अवैध खनन को रोकने के लिए ओपन पॉलिसी में ट्रैक्टरों को लाईसेंस प्रदान कर दिए जाएं। साथ ही निजी भूमि पर अवैध खनन करने वालों पर कार्यवाही की जाए।	उद्योग विभाग
4. श्री होशियार सिंह, देहरा		
1	पर्यटन तथा राजस्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रदेश तथा क्षेत्र में फिल्म ईन्डस्ट्री, कैसिनोज़ खोले जाएं। कैसिनोज़ में हिमाचलीयों के खेलने पर पूर्ण प्रतिबन्ध की व्यवस्था के साथ इनका संचालन केवल पर्यटकों के लिए किया जाए।	पर्यटन/ आयकर विभाग
2	प्रदेश में लाल चन्दन, सागबान तथा उच्च कीमत वाले पेड़ों को रोपित कर लगाया जाए।	वन विभाग
3	खैर के पेड़ को फुट की मात्रा में मापकर ठेकेदारों द्वारा खरीदा जाता है इसे लम्बाई तथा किलोग्राम पर स्थानीय लोगों द्वारा बेचा जाए इसी लम्बाई तथा किलोग्राम के हिसाब से ठेकेदार खरीदें इस बारे एक Research & Development Study की जाए।	वन विभाग
4	अवैध खनन को रोकने के लिए M-Form की क्षमता को बढ़ाया जाए। क्रशर पर कण्डे (धर्मकांटा/Weight Machine) का प्रावधान किया जाए। चैक पोस्टस जगह-जगह लगाई जाएं ताकि मटिरियल के भार को पुनः चैक किया जा सके। ओवरलोड गाड़ियों पर भारी कर लगाया जाए। रायल्टी के हिसाब से न कर टन के हिसाब से टैक्स / चार्ज लगाया जाए जिससे सरकार को पूरा राजस्व प्राप्त होगा।	Excise & Taxation/ परिवहन/ उद्योग विभाग
5	हिमाचल में प्लाई वुड उद्योग, पेपर उद्योग व अन्य उद्योग जो लकड़ी से सम्बन्धित है, स्थापित किए जाएं।	उद्योग /वन विभाग
6	मनाली से कांगड़ा डैम तक व्यास नदी की डिसिल्टिंग का कार्य किया जाए जिससे सरकार को बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होगा।	जल शक्ति/HPPCLtd./ Excise & Taxation
7	हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी मन्दिरों में वीआईपी दर्शन की सुविधा चलाई जाए और कम से कम नवरात्रों में तो यह सुविधा प्रदान की ही जानी चाहिए जिससे मन्दिरों की आय/राज्य आय में बढ़ोतरी होगी।	भाषा कला एवं संस्कृति विभाग/ समस्त उपायुक्त
8	पौंग डैम विस्थापितों के ज्वलंत मुददे में सभी परिवारों को किसी दूसरी जगह/प्रदेश में जमीन न दे कर उन्हें एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि वे वर्षो तक जमीन के मालिकाना हक के लिए न भटकें।	उपायुक्त कांगड़ा / राजस्व विभाग
9	पौंग डैम विस्थापित परिवारों के लगभग 140 मामले ऐसे हैं जिनमें DC Land को Forest Land कर दिया गयाहै इनकी दुरूस्ती के लिए लम्बित पड़े मामलों को अतिशीघ्र दुरूस्त किया जाए।	उपायुक्त/वन विभाग
10	जिला कांगड़ा में 15 निर्वाचन क्षेत्र पड़ते हैं जिसके दृष्टिगत कांगड़ा के तीन नये जिले बनाए जाएं।	
11	उच्च न्यायालय की एक बैंच जिला कांगड़ा में खोली जाए।	
12	निर्वाचन क्षेत्र को अपना बीडीओ कार्यालय दिया जाए तथा लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग के डिवीजन भी निर्वाचन क्षेत्र में ही प्रदान किए जाएं।	ग्रामीण विकास/लोक निर्माण/ जल शक्ति विभाग
13	लोक निर्माण विभाग तथा जल शक्ति विभाग के सर्कल भी निर्वाचन क्षेत्र में खोले जाएं।	लोक निर्माण/ जल शक्ति विभाग
14	निर्वाचन क्षेत्र की दो पंचायतें लुदरेट व एक अन्य के लिए पुलिस थाना ज्वाली दूर पड़ता है। इन दो पंचायतों के क्षेत्र को पुलिस थाना हरिपुर के क्षेत्र में शामिल किया जाए।	पुलिस /पंचायती राज विभाग

15	प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त सड़कों व अन्य योजनाओं के निर्माण हेतु 30 प्रतिशत धनराशि उपलब्ध करवाने की शर्त को पूरा किया जाए ताकि कम से कम इन योजनाओं के टैण्डर लग सकें।	लोक निर्माण/ जल शक्ति / सम्बन्धित विभाग
16	टुटडू–ढलियारा सड़क के लिए 1.5 करोड़ रू0 का प्रावधान किया जाए ताकि सड़क के कार्य को पूर्ण किया जा सके।	लोक निर्माण विभाग
17	विधायक प्राथमिकता बैठकों में दी जाने वाली presentation के कॉलम DPR awaited में यह भी दर्शाया जाए कि कौन सी डीपीआर किस स्तर पर तथा किस कारण से लम्बित है।	योजना विभाग
18	निर्वाचन क्षेत्र के लिए घोषित की गई दो पीएचसीज़ तथा इन्डोर स्टेडियम के लिए बजट का प्रावधान कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	स्वास्थ्य/ युवा खेल सेवाएं /सम्बन्धित विभाग
19	आपदा से प्रभावित स्थानों/मकानों/अन्य किसी का सर्वे करने के लिए पटवारी की जगह ईन्जीनियर को अधिकृत किया जाए।	राजस्व विभाग
5. श्री बिक्रम सिंह, जसवां–प्रागपुर		
1	विधायक प्राथमिकता बैठकों में दी जाने वाली presentation के कॉलम DPR awaited में यह भी दर्शाया जाए कि कौन सी डीपीआर किस स्तर पर तथा किस कारण से लम्बित है।	योजना विभाग
2	क्षेत्र में निर्माणाधीन पॉली वेटनरी के भवन के लिए 2.5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाए ताकि कार्य पूर्ण किया जा सके।	पशु पालन विभाग
3	राजकीय तकनीकी महाविद्यालय जंडौर के भवन का उदघाटन कर कक्षाएं आरम्भ की जाएं।	तकनीकी शिक्षा विभाग
4	औद्योगिक क्षेत्र चनौर में Infrastructure Development Fund का प्रावधान किया जाए ताकि मूलभूत सुविधाओं के साथ इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा सके।	उद्योग विभाग
5	संसारपुर HRTC बस डिपो के निर्माण के लिए धन का प्रावधान किया जाए।	HRTC/ परिवहन विभाग
6	एफसीए के मामलों में एक बार ही ऑब्जेक्शन लगना चाहिए और इन एफसीए के लम्बित मामलों को अविलम्ब प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।	वन विभाग
6. श्री संजय रतन, ज्वालामुखी		
1	ज्वालामुखी में आने वाले श्रद्धालुओं तथा स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए एडीबी या राज्य के माध्यम से ज्वालामुखी का सौन्दर्यकरण किया जाए तथा यात्रियों को ज्वालामुखी शहर में रोकने के लिए पार्किंग, बस स्टैण्ड, मॉल, ऑटो स्टैण्ड निर्माण, रहने की अच्छी सुविधा व अन्य गतिविधियों के साथ–साथ छोटे–छोटे स्थानीय मन्दिरों के विकास के कार्य एक मास्टर प्लान के साथ किए जाएं।	शहरी विकास/ भाषा कला एवं संस्कृति/ पर्यटन विभाग
2	हैलीपोर्ट का निर्माण नदौन तथा ज्वालामुखी के बीच कहीं भी जवालामुखी के नज़दीक किया जाए।	पर्यटन विभाग
3	निर्वाचन क्षेत्र में व्यास नदी के ऊपर अमतर, सुदौढ़ापतन तथा डिब के पास 3 पुलों का निर्माण किया जाए तथा नखेड़ खडड के ऊपर जन्दराह में बन रहे पुल के लिए 2 करोड़ रूपये का प्रावधान कर निर्माण कार्य को तीव्रगति से शीघ्रातिशीघ्र तैयार किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4	जल शक्ति विभाग में छोटी–2 सिंचाई योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान कर कार्यों को पूर्ण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
5	सूखाहार सिंचाई योजना की डी.पी.आर. को केन्द्र के माध्यम से शीघ्र स्वीकृत कर कार्य आरम्भ किया जाए ताकि क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके और वे ज्यादा से ज्यादा कृषि के क्षेत्र का विकास कर सकें।	जल शक्ति विभाग
6	नाबार्ड के अधीन बन रही पेयजल योजनाओं में धन का पूरा प्रावधान कर निर्माण कार्य पूरे किए जाएं ताकि स्थानीय जनता को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।	जल शक्ति विभाग

7	ज्वालामुखी के अन्तर्गत 51 पंचायतों के लिए बीडीओ कार्यालय ज्वालामुखी स्थित(at) सुराणी में खोला जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
8	निर्वाचन क्षेत्र ज्वालामुखी में लोक निर्माण तथा जल शक्ति विभागों के डिवीजन खोले जाएं।	जल शक्ति / लोक निर्माण विभाग
9	विद्युत विभाग का सर्कल कार्यालय ज्वालामुखी या देहरा में खोला जाए।	HPSEBLtd.
10	3 स्वीकृत सब–स्टेशनों ठेडा, मझीण तथा देहरियां का निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	HPTCLtd./ HPSEBLtd.
11	खुंडियां, मझीण तथा लगड़ू में बस स्टैण्ड का निर्माण किया जाए।	बस अडडा प्राधिकरण
12	लगड़ू नामक स्थान पर राजकीय महाविद्यालय खोला जाए।	शिक्षा विभाग
13	टिहरी में पॉलटेक्निक कॉलेज खोला जाए तथा 50 प्रतिशत दाखिले की शर्त को 40 प्रतिशत किया जाए ताकि अधिक से अधिक हिमाचली बच्चों को दाखिला प्राप्त हो सके।	तकनीकी शिक्षा विभाग
14	आई.टी.आई. खुंडियां में और ट्रेडों का संचालन किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
15	मझीण से दन्त चिकित्सक को deputation पर धर्मशाला भेजा गया है इन्हें पुनः मझीण में लगाया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
16	खुंडियां तथा ज्वालामुखी अस्पतालों को सुदृढ़ किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
17	पिछड़ी पंचायत पीढ़ी में पीएचसी खोली जाए।	स्वास्थ्य विभाग
18	क्षेत्र में पुलिस स्टेशन लगभग बन कर तैयार है इसके कार्य को पूर्ण करने के लिए 70–80 लाख रुपये प्रावधान कर सुचारू संचालन किया जाए।	पुलिस विभाग
19	नशे पर रोक लगाने के लिए सभी पुलिस कर्मचारियों को 5 साल थानों में तथा 5 साल बटालियन में सेंवाएं प्रदान करने की नीति बनाई जाए।	पुलिस विभाग
20	नाबार्ड धनराशि की सीमा को बढ़ाया जाए।	योजना विभाग
7. श्री केवल सिंह, शाहपुर		
1	सौंकणी दी कूहल का सुचारू संचालन किया जाए।	जल शक्ति विभाग
2	SCDP के अन्तर्गत निमार्णाधीन विश्राम गृह का कार्य 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है। एनएच क्षेत्र के बाहर से बनने के कारण इस भवन को अन्य सरकारी उपयोग में लाया जाए।	SOMA Deptt./ जल शक्ति विभाग
3	एडीबी के तहत बताला तथा नडडी क्षेत्र के लिए रू0 18 करोड़ को खर्च कर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
4	शाहपुर नगर परिषद सीवरेज परियोजना के लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान कर निर्माण कर पूर्ण किया जाए।	शहरी/ जल शक्ति विभाग
5	33 के.वी. सब–स्टेशन ध्रीणी के कार्य को शीघ्र पूर्ण कर चालू किया जाए।	HPPTCLtd/ HPSEBLtd.
6	विद्युत विभाग में फील्ड स्टाफ जैसे टीमेट इत्यादि और ट्रांसफार्मज़, कन्डक्टर/कनवर्टर, खम्बों की कमी को भी दूर किया जाए।	HPPTCLtd/ HPSEBLtd.
7	प्रताप सिंह कैरो आईटीआई शाहपुर को आधुनिक आईटीआई के रुप में जाना जाता है। इसे स्तरोन्नत कर इंजिनीयरिंग कॉलेज बनाया जाए तथा इसमें professional and job oriented degree courses ही चलाए जाएं और हर वर्ष इसके सुचारू संचालन के लिए उचित बजट का प्रावधान किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
8	पर्यटन की दृष्टि से ट्रैक रूटस करेरी, खब्बरूनाला वाटर फाल हारबोह तथस डलझील का सुधार /विस्तार/सुदृढ़ीकरण तथा सौन्दर्यकरण किया जाए और जब भी कर्मचारी/अधिकारी क्षेत्र में आते हैं तो विधायक से जरूर सम्पर्क करे ताकि योजनाओं को तैयार करने में आर रही किसी भी प्रकार की समस्या को स्थानीय जनता के सहयोग के साथ निपटाया जा सके।	पर्यटन/ समस्त सम्बन्धित विभाग
9	किसी भी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किये गए कार्यों को उसकी ACR में जोड़ा जाए।	समस्त विभाग

10	चम्बी खेल मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाए।	युवा खेल सेवाएं विभाग
11	सब्जी मण्डी गोरड़ा/चम्बी के लिए बजट का प्रावधान कर निर्माण कार्य आरम्भ/ पूर्ण किया जाए।	कृषि विभाग/ Agriculture Marketing Board
12	झुलाड़ नामक स्थान में लगभग 210 कनाल भूमि पर एग्रीकलचर फार्म है इसमें स्वीकृत पदों को बहाल कर भरा जाए।	कृषि विभाग
13	उद्यान विभाग के फार्म का सुदृढ़ीकरण किया जाए।	उद्यान विभाग
14	धर्मशाला से नडडी होते हुए सतोवरी–बरनेट–घेरा सड़क को पर्यटन की दृष्टि से प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
15	शाहपुर अस्पताल के अधूरे भवन निर्माण को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान कर कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
16	पीएचसी नागणबटट तथा सीएचसी लांझ के लिए भी बजट का पूरा प्रावधान कर निर्माण कार्य पूरे किए जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
17	चिकित्सकों के लिए बनाए जा रहे आवासीय परिसर के निर्माण कार्यों को रोककर उस धन को क्षेत्र क निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवनों के लिए उपयोग किया जाए। क्यांकि लपयाणा तथा ध्रीणी में बनाए गए आवासीय परिसरों में भी कोई नही रहता।	स्वास्थ्य विभाग
18	Veterinary Hospital शाहपुर तथा ध्रीणी के लिए उचित बजट प्रावधान कर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरे किए जाएं।	पशु पालन विभाग
19	सब–तहसील ध्रीणी तथा हारचक्कियां के लिए बजट का प्रावधान कर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरे किए जाएं।	राजस्व विभाग
20	क्षेत्र में गैस सिलेण्डर वितरित करने की नियमित सप्लाई के लिए प्रत्येक सप्ताह एक तारीख निश्चित की जाए कि इस तारीख को इस क्षेत्र में सप्लाई प्रदान की जाएगी ताकि क्षेत्रीय जनता को समय पर गैस आपूर्ति हो सके और उन्हें भी किसी समस्या का सामना न करना पड़े।	खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग
21	पुलिस चौकी लांझ तथा ध्रीणी के लिए उचित बजट प्रावधान कर सुचारू संचालन किया जाए।	पुलिस विभाग
22	भांग की खेती को वैध करने के लिए कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार नीति निर्मित करे।	कृषि विभाग
9. जिला कुल्लू		
1. श्री भुवनेश्वर गौड़, मनाली		
1	बाई पास मनाली के निर्माण में वन आपत्तियों का निपटारा कर शीघ्र निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण /वन विभाग
2	लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारी विधायक के बुलाने पर भी नहीं आते इस बारे उचित कार्यवाही की जाए।	लोक निर्माण
3	डबल लेन सड़क कुल्लू–मनानी बांई तरफ से बननी है इसमें अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिए क्षेत्रीय जनता को उचित मुआवजा दिया जाए।	लोक निर्माण/ राजस्व विभाग
4	पतलीकूहल सीएचसी तथा सर्किट हाउस मनाली के लिए नगर एवं ग्राम योजना विभाग इसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करे।	नगर एवं ग्राम योजना/ शहरी विकास विभाग
5	पतलीकूहल सीएचसी में एक एमओ डेन्टल को नियुक्त किया जाए और ईएनटी तथा गाईनी चिकित्सकों के पदों की स्वीकृति प्रदान की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
6	बरसात में क्षतिग्रस्त लिंक सड़कों को बस योग्य संचालन हेतु ठीक किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7	मनाली को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए 2–3 रोपवेज़ का निर्माण किया जाए।	RTDC (Ropeways)

8	पर्यटन की दृष्टि से ही दूर–दराज के क्षेत्रों में Tourist Villages का निर्माण किया जाए (with the help of Co-operative Societies)|	पर्यटन/पंचायती राज /ग्रामीण विकास विभाग
2. श्री सुरेन्द्र शौरी, बन्जार		
1	एनएच–305 का निर्माण कार्य पिछले 5–6 वर्षो से चल रहा है, सड़क चौड़ी भी काफी हुई है लेकिन सड़क को केवल बीच से पक्का किया गया है। फिल्हाल बंजार–जीभी तथा सोझा तक टारिंग का पूरा (बीच के साथ दांई और बांई ओर) कार्य किया जाए ताकि वाल्वो बसों और अन्य वाहनों का सुचारू संचालन हो सके और इस एनएच–305 सड़क की टारिंग के लिए विभाग अलग से एक टारिंग की डीपीआर तैयार कर केन्द्र को स्वीकृति हेतु भेजे।	लोक निर्माण विभाग
2	क्षेत्र में बिजली की लो वोल्टेज की समस्या का हल किया जाए और लारजी या बालीचौकी के बीच एक EHD Sub-Station का निर्माण किया जाए।	HPSEBLtd./ HPPTCLtd.
3	बरसात में क्षतिग्रस्त एनएच के साथ–2 लिंक सड़कों को ठीक करने के लिए विभाग लोगों की भूमि का अधिग्रहण (क्षतिग्रस्त भाग पर) करे।	लोक निर्माण विभाग
4	सिविल अस्पताल बंजार में चिकित्सकों के पूरे पद प्रदान किए जाएं तथा अस्पताल को 50 से 100 बिस्तर करने की रदद अधिसूचना को भी बहाल किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5	पिछले 6–7 वर्षो से निर्मित हो रहे दलासनी पुल के कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
6	बंजार बाईपास निर्माण के लिए शेष भूमि का अधिग्रहण कर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7	पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए बंजार में ट्रैफिक विंग खोली जाए।	पुलिस विभाग
8	अनछूहे पर्यटन स्थलों जैसे तीर्थन वैली, जिभी–शोझा, जलोड़ी के साथ गाड़ा गुशैणी, दयार, गड़सा का क्षेत्र है वहां पर बाहर के लोगों द्वारा 6–7 मंजिलें भवनों का निर्माण किया जा रहा है इसे रोका जाए तथा निर्वाचन क्षेत्र के साथ पूरे प्रदेश में केवल 5–6 कमरों के निर्माण (Eco friendly) की ही अनुमति मिले ताकि पर्यावरण सुरक्षित व सुन्दर बना रहे।	पर्यटन / पंचायती राज विभाग
3. श्री लोकेन्द्र कुमार, आनी		
1	एन.एच. 305 सैंज–औट–लुहरी (92कि0मी0) तथा शमशर–सेंज–आनी सड़क की दयनीय स्थिति में सुधार कर गुणवत्ता के साथ टारिंग/मैटलिंग व अन्य कार्य किए जाएं।	लो0नि0 विभाग
2	धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से श्रीखण्ड महादेव यात्रा का सुधारीकरण किया जाए।	भाषा, कला एवं संस्कृति/पर्यटन विभाग/ उपायुक्त कुल्लू
3	नशे पर पूर्ण रोक लगाने के लिए क्षेत्र में पुलिस बल को बढ़ाया जाए और जाम की समस्या से निपटने के लिए आनी में ट्रैफिक विंग खोली जाए जिसके लिए अलग से ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाए।	पुलिस विभाग
4	पर्यटन की दृष्टि से जलोड़ी पास तथा बागासराहन के क्षेत्र को विकसित किया जाए।	पर्यटन विभाग
5	पर्यटन की दृष्टि से जलोड़ी पास से रघुपुरगढ़ तथा जलोड़ी पास से सरयोरसर झील तक ब्राईडल पाथ का निर्माण कर ईलैक्ट्रिक बसों को चलाया जाए।	लोक निर्माण/ वन/ परिवहन/ पर्यटन विभाग
6	सीए स्टोर निरमण्ड तथा आनी में बन रहे हैं इन्हें सरकार के स्तर पर निर्मित किया जाए।	उद्यान/कृषि विभाग

7	दूध में डिग्री तथा फैट के नाम पर विभाग के लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं तथा दूध का मूल्य 20–21 रू0 दिया जा रहा है। मिल्क फैडरेशन तथा पशु पालन विभाग इस पर गौर करे और न्यूनतम कीमत तय की जाए।	पशु पालन विभाग/ HP Milk Fedration
8	बरसात में क्षतिग्रस्त लिंक सड़कों को शीघ्र ठीक किया जाए ताकि लोगों को बस की सुविधा मिल सके।	लोक निर्माण विभाग
9	आनी बाजार में आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों के लगभग 4 परिवारों के पास एक ईंच भूमि भी नहीं बची है। इन्हे नई जगह पर 2–3 बिस्वा भूमि प्रदान कर गृह निर्माण किया जाए।	राजस्व/वन विभाग/ उपायुक्त
10	क्षेत्र में बिजली की लो वोल्टेज की समस्या को हल किया जाए तथा ट्रांसफार्मरों की कमी को दूर किया जाए।	HPSEBLtd./ HPPTCLtd.
11	एपीएमसी सब्जी मण्डी आनी में बन रही है। अगली बरसात से पहले–2 दूसरी तरफ से Protection Wall लगाई जाए।	उद्यान विभाग/ APMC/ Agriculture Marketing Board
12	आनी से दिल्ली तथा शिमला के लिए सरकारी बस सेवा का संचालन दोपहर 1–2 बजे के बाद भी किया जाए।	HRTC/परिवहन विभाग
10.जिला शिमला		
1. श्री बलबीर सिंह वर्मा, चौपाल		
1	विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत प्रस्तावित अपग्रेडेशन/मैटलिंग / टारिंग की डी.पी.आरज़. को प्राथमिकता के आधार पर तैयार तथा स्वीकृत करवाकर कार्य आरम्भ/ पूर्ण किए जाएं।	लोक निर्माण विभाग
2	बरसात में क्षतिग्रस्त हुई लगभग 18 सड़कों को शीघ्र ठीक किया जाए ताकि इनमें बसों की सुविधा लोगों को प्रदान की जा सके।	लोक निर्माण विभाग
3	नया परिवहन विभाग डिपो नेरवा में खुला है इसका पूरा संचालन तारोदवी के स्थान पर नेरवा से ही किया जाए तथा भवन निर्माण कार्य आरम्भ/पूर्ण किया जाए और बसों का संचालन नेरवा डिपो के नाम से किया जाए।	परिवहन/ वन विभाग
4	चौपाल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पुरानी बसों के बजाय नई बसें प्रदान की जाएं।	HRTC
5	जल शक्ति विभाग में बन रही योजनाओं के कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए और छोटी–2 स्कीमों के लिए छोटी–2 खडडों से पानी न उठाकर टौंस नदी से पानी उठाकर योजनाएं चलाई जाएं ताकि पानी की कमी न हो।	जल शक्ति विभाग
6	किसी भी योजना के कार्य का सबलेट न किया जाए।	लोक निमार्ण/ जल शक्ति/ सम्बन्धित विभाग
7	पर्यटन की दृष्टि से चौपाल में पर्यटन विभाग का कैफे/भोजनालय खोला जाए और फौरेस्ट कॉरिडोर (50–60 कि0मी0) में चौपाल को विकसित किया जाए।	पर्यटन / वन विभाग
8	देहां से खिड़की तथा धनौट से देहां सड़क को सीआरएफ में दुरूस्त किया जाए जिसमें एक पुल भी बनाया जाए।	लोक निर्माण विभाग
9	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वितीय चरण में बन रही 12 सड़कों को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
10	निर्वाचन क्षेत्र में पंचायतों को DC Fund से दी जाने वाली धनराशि का आवंटन समान रूप से किया जाए।	उपायुक्त शिमला
11	पिछड़ी पंचायत कुपवी के लिए धनराशि कम मिली है इसे लाख–लाख रू0 किया जाए।	पंचायती राज/ राजस्व/ योजना विभाग/ उपायुक्त शिमला
12	लोक निर्माण विभाग के डिवीजन खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	लोक निर्माण विभाग

13	शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सभी स्टाफ की कमी को दूर किया जाए।	शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा/ स्वास्थ्य/ सम्बन्धित विभाग
14	कुपवी, चौपाल तथा नेरवा अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की मशीनें प्रदान की जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
15	चौपाल में पानी की कमी को दूर किया जाए और तैयार योजनाओं का उदघाटन कर जनता को इनका लाभ प्रदान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
16	विधायक प्राथमिकता योजनाओं में विधायकों द्वारा दी गई योजनाओं में विधायकों का नाम लिखा जाए।	लोक निर्माण/ जल शक्ति/ समस्त सम्बन्धित विभाग
	2. श्री कुलदीप सिंह राठौर, ठियोग	
1	भारी बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों को डंगे लगाकर शीघ्र ठीक किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2	सड़कों (एनएच/लोक निर्माण/ पंचायत/ अन्य माध्यम से बनी हुई) में जल निकासी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कलवर्ट बन्द न हों।	लोक निर्माण विभाग
3	विभागों को जल भण्डारण की ओर ध्यान देकर बड़ी योजना का निर्माण करना चाहिए।	जल शक्ति / पंचायती राज विभाग
4	कुरपण खडड के प्रथम चरण का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है शेष कार्य को पूर्ण कर जनता को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाए।	जल शक्ति विभाग
5	क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों कोटगढ़, कुमारसैन, ठियोग व अन्य में चिकित्सकों के साथ–साथ अन्य स्टाफ की कमी को दूर किया जाए	स्वास्थ्य विभाग
6	ठियोग में अल्ट्रासाउंड की मशीन प्रदान की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
7	ठियोग में जिला अस्पताल का निर्माण किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
8	नारकण्डा से हाटू रोपवे का निर्माण कार्य भारतमाला के अन्तर्गत आरम्भ किया जाए।	RTDC (Ropeways)
9	नारकण्डा में बन रहे स्केटिंग रिंक के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए बजट का उचित प्रावधान किया जाए।	युवा खेल सेवाएं / वन/ पर्यटन विभाग
10	सब–तहसील बड़ागांव तथा मतयाणा खोलने की जो अधिसूचना रदद की गई है उसे बहाल किया जाए।	राजस्व विभाग
11	नशे पर रोक लगाने के लिए पुलिस थानों को सुदृढ़ीकरण करने के साथ–साथ पूरे स्टाफ की नियुक्ति भी जाए।	पुलिस विभाग
12	ननखड़ी के जरोल टिक्कर जो नशे का गढ़ बनता जा रहा है पर विशेष ध्यान दिया जाए।	पुलिस विभाग
13	ननखड़ी/टिक्कर में लोक निर्माण विभाग की हट है जो 4–5 साल से बन्द पड़ी है यहां पर पुलिस विभाग की चौकी खोली जाए।	पुलिस/ लोक निर्माण विभाग
14	सड़को की गुणवत्ता विभाग सुनिश्चित करे और पिछले कई वर्षो से चल रहे कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करे।	लोक निर्माण विभाग
15	सड़कों के कार्यो को ठेकेदार द्वारा सबलेट नहीं किया जाना चाहिए यदि किया जाता है तो उचित कार्यवाही की जाए।	लोक निर्माण विभाग
	3. श्री नन्द लाल, रामपुर	
1	विधायक प्राथमिकता में प्रस्तावित गत 5–6 वर्षो की डी.पी.आर. को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए। यदि विभाग इन डी.पी.आरज़. को शीघ्र तैयार करने में सक्षम नही है तो इन डी. पी.आरज़. को प्रोफेशलन ऐजैन्सी के माध्यम से अतिशीघ्र तैयार किया जाए।	लो0नि0/ जल शक्ति विभाग
2	नन्ती–टिक्कर की डी.पी.आर. को तैयार कर शीघ्र स्वीकृत किया जाए ताकि स्थानीय जनता को सड़क सुविधा से जोड़ा जा सके।	लो0नि0 विभाग
3	ननखड़ी–रामपुर की जीवनरेखा, टिक्कर–खमाडी सड़क 52 कि0मी0 की दयनीय स्थिति को सुधारा जाए। इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी पड़ती है जिससे हर साल यह सड़क खराब हो जाती है इसलिए	लो0नि0 विभाग

	हर वर्ष/दो वर्ष के अन्तराल पर इसकी मै0/टा0 का कार्य नियमित रूप से किया जाए। साथ ही इस सड़क की मुरम्मत की 2 डी. पी.आर. केन्द्र को प्रस्तावित है को शीघ्र स्वीकृत कर मुरम्मत कार्य गुणवत्ता के साथ आरम्भ/पूरा किया जाए।	
4	रामपुर में जाम की समस्या को हल करने के लिए बस स्टैण्ड से आगे की तरफ (across the river) विधायक प्राथमिकता में प्रस्तावित पुल का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र किया जाए जिसके लिए प्रोजेक्ट से भी वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।	लो0नि0 विभाग
5	सराहन मन्दिर से बशनकंडा रोपवे(रोपवे ट्राली) का निर्माण किया जाए।	RTDC (Ropeways)
6	कोटला इंजिनीयरिंग कॉलेज के भवन निर्माण कार्य को तीव्रगति (Expedite) से पूर्ण कर सभी ट्रेड की कक्षाओं का सुचारू संचालन सुन्दरनगर के स्थान पर इसी कॉलेज से किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
7	रा0व0मा0 पाठशाला टिप्पर–मझोली, शोली, कुंगलबाल्टी तथा खमाडी के निर्माणाधीन भवनों के कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग
8	स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगभग 5–6 साल से बन रहे ट्रामा सेन्टर खनेरी के लम्बित कार्य को शीघ्र पूर्ण कर स्थानीय जनता को इसे समर्पित किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
9	सब्जी मण्डी डकोलर, रामपुर का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	Agriculture Marketing Board
10	सीए स्टोर दतनगर, रामपुर एरिया में एनएच के साथ बद्राश में निर्मित किया जाए।	उद्यान विभाग/ HPMC
11	राजकीय महाविद्यालय ननखड़ी के भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए। साथ की ज्यूरी कॉलेज की कक्षाएं अन्य स्थान पर अन्य भवन में चल रही हैं शीघ्र ही इस महाविद्यालय का भवन निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए जिसके लिए भूमि (Sheep Breeding Farm) भी उपलब्ध है।	शिक्षा/ विभाग
12	कॉलेजों में तैयार साईंस ब्लॉकों का उदघाटन कर इन्हें जनता को समर्पित किया जाए।	शिक्षा विभाग
13	स्पोर्टस हॉस्टल दतनगर में तैयार है इसका भी उदघाटन कर जनता को समर्पित किया जाए।	युवा खेल सेवाएं विभाग
14	पीएचसी लालसा–चिकसा का भवन तैयार है इसमें विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाए और जनता को इसे समर्पित किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
15	आईटीआई जो प्राईवेट भवन में चल रही है इसके निर्माण के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। शीघ्र ही इसके भवन निर्माण कार्य को आरम्भ किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
16	रामपुर क्षेत्र के लिए नई बसें प्रदान की जाएं।	HRTC
17	बरसात से क्षेत्र में गॉंव के गॉंव धंस गये हैं लोगों को मकान बनाने के लिए 3–4 बिस्वा भूमि दी जा रही है उस भूमि को सुरक्षित जगह पर दिया जाए।	राजस्व/वन विभाग
18	विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत ड्रेनेज की प्राथमिकता देने पर विभाग विचार करे।	योजना विभाग
11. जिला मण्डी		
1. श्री दीप राज, करसोग		
1	बखरौड़ से कोटलू सड़क तथा चौरीधार से कोटलू सड़क के निर्माण कार्य का पूरा बजट उपलब्ध करवाकर कार्यों को पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
2	सेरी–कटाण्डा–महोग सड़क पर आधे–अधूरे लगाए जा रहे डंगों को पूरा कर बसों की आवाजाही के लिए चालू किया जाए।	लोक निर्माण/परिवहन विभाग/ HRTC

3	तत्तापानी से करसोग सड़क पर लगाए गये क्रैश बैरियरस को Dark Spot पर न लगाकर आगे–पीछे लगाया गया है। इन्हें Dark Spot पर लगाकर दुरूस्त किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
4	पुन्नी पंचायत में SCDP के तहत स्कूल को जाने वाली सड़क पर बना पुल भारी बरसात से बह गया था। इस पुल का निर्माण शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।	लोक निर्माण/ SOMA Deptts.
5	निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 35 कि0मी0 के क्षेत्र को जोड़ने के लिए मांझु–मघाण नामक स्थान पर पुल का निर्माण किया जाए जहां आज भी लोग झूला पुल का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है।	लोक निर्माण विभाग
6	करसोग के लिए 64 रूट पर नई बसें प्रदान की जाएं।	HRTC
7	करसोग में जाम की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए वरल के पास शनि मन्दिर के नजदीक स्थान/भूमि भी उपलब्ध है। यहां पर एक पार्किंग का निर्माण किया जाए।	शहरी विकास विभाग
8	तत्तापानी का पर्यटन की दृष्टि से और विकसित किया जाए तथा निर्माणाधीन घाटों के कार्यों को पूर्ण किया जाए।	पर्यटन विभाग
9	करसोग अस्पताल में चिकित्सकों के सभी पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए और सभी प्रकार के उपकरण उपलबध करवाए जाएं।	स्वास्थ्य विभाग
10	डीएसपी कार्यालयों में कॉलट्रेस करने की सुविधा के साथ–साथ अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस कर इनका सुदृढ़ीकरण किया जाए।	पुलिस विभाग
11	निर्वाचन क्षेत्र करसोग के अधीन जितने भी स्कूलों (Primary, Middle, High, Sr. Sec.) का अपग्रेड किया गया है उन स्कलों में बैठने की उचित व्यवस्था के साथ–साथ शौचालयों की उचित तथा स्वच्छ व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए।	शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
12	विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत पिछले 3–4 वर्षो की प्राथमिकताओं की डीपीआरज़. को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।	लोक निर्माण/ जल शक्ति विभाग
13	शिक्षा के क्षेत्र को सुद्बढ़ करने के लिए करसोग में अच्छा केन्द्रीय विद्यालय खोलने की प्रस्तावना को शीघ्र स्वीकृत करवाकर निर्माण कार्य आरम्भ किया जाए।	शिक्षा विभाग
	2. श्री विनोद कुमार, नाचन	
1	अटल आदर्श विद्यालय गडारी के कार्य को पूर्ण करने के लिए उचित बजट लगभग 70 करोड़ की व्यवस्था कर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग
2	रा0व0मा0 पाठशालाएं मौंवीं सेरी तथा किर्लीग में साईंस लैब निर्माण हेतु वर्ष 2022–23 में 25–25 लाख रू0 का प्रावधान किया गया था इनके निर्माण कार्यों को शीघ्र आरम्भ/पूरा किया जाए जिसके लिए मौंवीं सेरी के लिए 5 बीघा तथा किर्लीग के लिए 2.5–3 बीघा भूमि भी उपलब्ध है।	शिक्षा विभाग
3	रा0व0मा0 पाठशालाएं चैलचौक तथा हथगढ़ में खेल मैदान बनाने के लिए वर्ष 2022–23 में 50–50 लाख रू0 का प्रावधान किया गया था। इन खेल मैदानों के टैण्डर लगाकर निर्माण कर शीघ्र आरम्भ/पूरा किये जाएं।	शिक्षा/लोक निर्माण/ युवा खेल सेवाएं विभाग
4	प्राथमिक पाठशाला देवीधड़ तथा चौकड़ी में लगने वाली सुरक्षा दीवार का निर्माण शीघ्र किया जाए। इस दीवार के निर्माण से छोटे बच्चों को खेलने के लिए मैदान भी बन जाएगा।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
5	गोलण हाई स्कूल की छत को रिपेयर कर नई छत लगाई जाए।	शिक्षा विभाग
6	विधान सभा क्षेत्र के 31 स्कूल ऐसे हैं जहां एक–एक अध्यापक कार्य कर रहा है। अध्यापकों की कमी को दूर किया जाए।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

7	प्राथमिक विद्यालय कुटासनी, सेगरा गलु, भुण्डल, नालू, कोटला तथा खरलोह में एक भी अध्यापक नहीं है इन स्कूलों में फिलहाल कम से कम एक-एक अध्यापक को ही नियुक्त कर दिया जाए।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
8	बस स्टैण्ड गोहर तथा चैलचौक की एफ.सी.ए. शीघ्र प्रदान कर निर्माण कार्य आरम्भ किए जाएं। इन बस स्टैण्डों के लिए 1.5 करोड़ रू0 तथा 1.37 करोड़ रू0 भी उपलब्ध है।	वन विभाग/ बस अडडा प्राधिकरण
9	वन विश्राम गृह जाच्छ का निर्माण कार्य घटिया तरीके (poor quality work) से किया जा रहा है इसकी जाँच की जाए और कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।	वन विभाग
10	विश्राम गृह देवीधड़ बन कर तैयार है इसके लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जाए।	वन/लोक निर्माण/ सम्बन्धित विभाग
11	जल शक्ति विभाग के डिवीजनों बग्गी तथा सुन्दरनगर में 1/2 ईंच की पाईपों की कमी को दूर किया जाए ताकि जिन गरीब लोगों को कनैक्शन मिल गये हैं उन्हें तो कम से कम पानी की सुविधा प्रदान की जा सके।	जल शक्ति विभाग
12	किसान भवन सियांज तथा तरौर के लिए धन का प्रावधान कर निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ/पूरा किये जाएं।	कृषि विभाग
13	लोक निर्माण विश्राम गृह धनोटू के निर्माण कार्य को पूर्ण कर चालू किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
14	कमरूनाग हैलीपैड के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग के माध्यम से 25 लाख का प्रावधान किया गया था इसके निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए।	पर्यटन विभाग
15	निर्वाचन क्षेत्रों की पंचायतों में स्लैब कलवर्ट बनकर तैयार है इनकी एपरोचिज़ के कार्य को शीघ्र पूरा किया जाए ताकि स्थानीय जनता को इनका लाभ प्राप्त हो सके जैसे ग्राम पंचायत घरोट, तुन्ना की सेरी, सियांज पंचायत के पंगलेहड़, छपराहण पंचायत के छोल, भुलाण पंचायत के नालू में इत्यादि।	पंचायती राज/ ग्रामीण विकास/ लोक निर्माण विभाग
16	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की मुरम्मत तथा रख-रखाव के लिए धन का प्रावधान किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
17	चैलचौक से पन्डोह सड़क को सीआरएफ में पहली प्राथमिकता के तौर पर स्वीकृत कर इसका जीर्णोद्वार /सुधार/विस्तार किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
18	पीएचसी चौक में प्रतिदिन 200 की ओपीडी है इसकी रदद अधिसूचना को बहाल कर डॉक्टरों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थ्य विभाग
19	सिवील अस्पताल गोहर को आदर्श स्वास्थ्य संस्थाना बनाना है इसलिए मापदण्डों के अनुरूप यहां पर 6 डॉक्टर (सर्जन, गाईनी, आर्थो इत्यादि) के सभी पदों पर डॉक्टरों को नियुक्त किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
20	निर्वाचन क्षेत्र में विद्यमान सभी स्वास्थ्य संस्थानों चाहे एचसी, पीएचसी, सीएचसी इत्यादि में डॉक्टरों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थ्य/ आयर्वेदा विभाग
21	एडीबी के तहत बने शिवा प्रोजेक्ट के सभी 8 कलस्टरों में किसानों के खेतों में लगाए गए सभी पौधे पानी की कमी के कारण सूख रहे हैं। यहाँ सिंचाई की व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए क्योंकि अगले चरण में यहाँ अभी और प्लांटेन्शन होनी है।	जल शक्ति/ उद्यान विभाग(HPSHIVA)
22	पर्यटन की दृष्टि से ज्यूणी वैली की ग्राम पंचायत लोट के डुंगाथर में पैराग्लाईडिंग की साईट तक सड़क निर्माण हेतु बजट का प्रावधान कर निर्माण कार्य आरम्भ/पूरा किया जाए।	पर्यटन/लोक निर्माण विभाग
23	भारी बरसात के कारण ग्राम पंचायत सियांज, छपराहण तथा नान्डी में बहे 6 पैदल पुलों (5 वन विभाग+ 1 पंचायत द्वारा निर्मित) को जनहित में शीघ्र बनाया (restore) जाए।	वन/ पंचायती राज/ लोक निर्माण विभाग/ उपायुक्त

3. श्री ईन्द्र सिंह गॉंधी, बल्ह		
1	मेडिकल कॉलेज नेरचौक में बिजली की व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए।	HPSEBLtd./ स्वास्थ्य विभाग
2	विद्युत विभाग के मण्डलीय कार्यालय नेरचौक को खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	HPSEBLtd.
3	आईटीआई रिवालसर को खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
4	पुलिस चौकी रिवालसर को थाना बनाने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	पुलिस विभाग
5	पशु चिकित्सालय दुर्गापुर खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	पशु पालन विभाग
6	सरकाघाट–हमीरपुर सड़क के अन्तर्गत कलखर–नेरचौक सड़क को चौड़ा (विस्तारीकरण) किया जाए।	लो0नि0 विभाग
7	मण्डी–बैहना से नलसर वाया गागल सड़क का विस्तारीकरण कर इसे टू–लेन किया जाए।	लो0नि0 विभाग
8	बल्ह वैली मिडीयम ईरीगेशन प्रोजेक्ट का सुधार कर (ओपन चैनल के स्थान पर पाईपें लगाकर) गॉंव के अन्तिम छोर पर बैठे किसानों को भी पानी की सुविधा प्रदान की जाए।	जल शक्ति विभाग
9	बीबीएमबी से 15 पंचायतों के लिए उठाऊ पेयजल योजना के राईजिंग मेन व अन्य शेष कार्य को पूर्ण कर चालू किया जाए।	जल शक्ति विभाग
10	केरल विधान सभा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश विधान सभा का जीर्णोद्धार / नया भवन निर्मित किया जाए ताकि 25–30 साल तक मुरम्मत की आवश्यकता न पड़े।	हि0प्र0 विधान सभा
11	पर्यटन की दृष्टि से रिवालसर, कुंतभयो तथा नलसर झील का विस्तारीकरण/ सौन्दर्यकरण किया जाए ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी प्राप्त हो सके।	पर्यटन विभाग
12	ढांगू कूहल में प्रत्येक वर्ष धन खर्च किया जाता है लेकिन अभी तक किसानों को सिंचाई हेतु पानी नही मिलता। इस सम्बन्ध में विभाग उचित कार्यवाही करे।	जल शक्ति विभाग
13	बैहना नाला का तटीयकरण करने के लिए टैण्डरज़. की सबलेटिंग न की जाए।	जल शक्ति विभाग
14	सेगल/सेकड़ नाला के तटीयकरण के टैण्डरज़ वर्ष 2022 में हुए थे लेकिन कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है। इसके कार्य को शीघ्र गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए और टैण्डरज़ की सबलेटिंग न की जाए।	जल शक्ति विभाग
15	बल्ह में किसी भी विभाग का एक विश्राम गृह खोला जाए।	लोक निर्माण/ वन/ जल शक्ति/ सम्बन्धित विभाग
16	क्षेत्र के लोगों को तीन महीने से मनरेगा की दिहाड़ी नहीं मिल रही है इसे जारी किया जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
17	रा0व0मा0 पाठशाला घासणू के रेत बजरी के 40 लाख रू0 दिए जाएं और बाउन्डरी वॉल, शौचालयों इत्यादि का निर्माण किया जाए।	शिक्षा विभाग
18	रा0व0मा0 पाठशाला सरकीधार में बरसात के कारण स्कूल भवन नीचे आ गया है बच्चे टीन के शैड में पढ़ रहे हैं नये भवन का निर्माण शीघ्र किया जाए।	शिक्षा विभाग
19	ग्राम पंचायत बढियाल में किशोर नामक व्यक्ति का मकान पूरा चला गया उसे मिला 1 लाख रू0 और साथ वाले भाई का मकान नहीं गिरा उसे मिले 3 लाख रू0, सुखराम नामक व्यक्ति का नुकसान हुआ उसे मिले 10 हजार रू0 तथा जिसका कुछ नहीं गया उसे मिला 40 हजार रू0 इस बारे उचित कार्यवाही की जाए।	ग्रामीण विकास/ पंचायती राज विभाग/ राजस्व विभाग/ उपायुक्त मण्डी

4. श्री दलीप ठाकुर, सरकाघाट		
1	सरकाघाट तथा बलद्वाड़ा अस्पताल में स्पेसिलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
2	निर्वाचन क्षेत्र की पीएचसीज़. तथा सीएचसीज़. में भी डॉक्टरों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।	स्वास्थय विभाग
3	बलद्वाड़ा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था की जाए।	स्वास्थ्य विभाग
4	सरकाघाट तथा बलद्वाड़ा अस्पताल में ओपीडी भवन लगभग बनकर तैयार है इनके लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाकर निर्माण कार्य पूर्ण कर इनका उदघाटन कर जनता को समर्पित किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
5	लोक निर्माण विभाग के बलद्वाड़ा, सरकाघाट तथा भदरोता इत्यादि सब–डिवीजनों में जेई के रिक्त चल रहे पदों को भरा जाए।	लोक निर्माण विभाग
6	लोक निर्माण विभाग का मुख्य अभियन्ता कार्यालय (Chief office) को सरकाघाट में खोला जाए/किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
7	मण्डी की तरफ पड़ने वाले गाँवों जैसे तालाब, सुलफर, पौंटा, हरिगैहरा आदि को बाढ़ से बचाने के लिए सीरखडड का तटीयकरण किया जाए।	जल शक्ति विभाग
8	बरसात से क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों जैसे कलथर–बाणु–बलद्वाड़ा सड़क, ढलौण–चन्द्रास सड़क इत्यादि को अतिशीघ्र ठीक किया जाए, डंगे लगाए जाएं ताकि बसों का सुचारू संचालन किया जा सके।	लोक निर्माण विभाग
9	क्षेत्र में निर्मित 4 पुलों भांवला, कलथर, नारला तथा पपलोग के एपरोचिज़ कार्य/बीम कार्य/ अन्य शेष कार्यों को पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
10	सरकाघाट बस डिपो का सुधार किया जाए और इस डिपो से बल्ह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ लगती 16 पंचायतों भदरोता व दुर्गापुर आदि के क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त बसों की सुविधा प्रदान की जाए।	HRTC
11	सरकाघाट से बिलासपुर एम्स के लिए तथा चण्डीगढ़ के लिए 2 बसों का संचालन किया जाए।	HRTC
12	भारी बरसात की त्रासदी में पटड़ीघाट के पास के मिडल स्कूल ज्वाली के क्षतिग्रस्त भवन को पुनः निर्मित किया जाए।	शिक्षा विभाग
13	क्षेत्र के 4 स्कूलों पटड़ीघाट, चौक, कसमैला, देवभ्रता में साईंस लैबों के निर्माण कार्य को शीघ्र आरम्भ /पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग
14	सरकाघाट–रोपड़ी–रिशा–धवाणु, खलियाणा–डल, धबोई–कैहरी–बलद्वाड़ा इत्यादि सड़कों की मैटलिंग/ टारिंग का कार्य गुणवत्ता के साथ किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
15	पॉलटेक्निक कॉलेज खोलने की रदद की गई अधिसूचना को बहाल किया जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
16	भदरोता में मिनी सचिवालय खोला जाए।	राजस्व विभाग
17	क्षेत्र की 16 पंचायतों के लिए भदरोता में पुलिस चौकी खोली जाए।	पुलिस विभाग
18	विभागीय अधिकारी विधायक के साथ फील्ड में चलें और योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त करें।	लोक निर्माण/ जल शक्ति/ समस्त सम्बन्धित विभाग
19	विधायक प्राथमिकता में बलद्वाड़ा क्षेत्र के लिए दी गई बहाव सिंचाई (कूहल) की योजना की डी.पी.आर. को शीघ्र बनाकर कार्य आरम्भ करे और जो बाँध टूट गया है उसकी शीघ्र मुरम्मत करे।	जल शक्ति विभाग

<u>माननीय मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद प्रस्ताव</u>

दो दिवसीय बैठकों के अन्त में मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि इन दो दिवसीय बैठकों में 68 विधायकों में से 51 माननीय विधायकों ने भाग लिया । बैठकों में प्रदेश महत्व के विभिन्न मुद्दे माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए हैं । कुछ मुद्दों पर बैठकों में ही निर्णय लिए गए हैं । अन्य मुद्दों पर विभाग तुरन्त कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से सरकार को अवगत करवाएंगे। मुख्य सचिव मन्त्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक क्षेत्र का समान विकास किया जाएगा तथा विकास में रही त्रुटियों को दूर किया जाएगा।

बैठकों के समापन पर मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश ने माननीय मुख्य मन्त्री, उप–मुख्यमंत्री, मन्त्रीगण, मुख्य संसदीय सचिवों, विधायकों, समस्त प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, सभी उपायुक्तों व उपस्थित अन्य अधिकारियों का दो दिवसीय बैठकों में भाग लेने के लिए धन्यवाद किया तथा स्पष्ट किया कि दो दिवसीय बैठकों में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों का सभी विभागों द्वारा तुरन्त एवं पूर्णतः से पालन किया जाएगा । प्रदेश के चहूंमुखी तथा समाज के सभी वर्गों के त्वरित व सन्तुलित विकास के लिए सम्पूर्ण प्रशासन सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान करेगा । सभी सम्बन्धित विभाग बैठकों में लिए गए निर्णयों एवं माननीय विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही से सम्बन्धित माननीय विधायकों तथा योजना विभाग मुख्यालय को समयबद्ध सीमा में अवगत करेंगे। दो दिवसीय बैठकें धन्यवाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुईं।

दो दिवसीय बैठकों में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देश

क्र. सं.	माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के निर्देश	सम्बन्धित विभाग
1.	विधानसभा के अगले सत्र में हमारी सरकार Transparency Act ला रही है जोकि सभी अधिकारियों तथा राजनैतिक लोगों पर भी लागू होगा।	सामान्य प्रशासन/ समस्त सम्बन्धित विभाग
2.	वर्ष 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाना है।	परिवहन/ऊर्जा विभाग/HPPCLtd
3.	स्वां नदी चैनेलाईजेशन लगभग 1200 करोड़ रू0 से दो चरणों में किया गया है। यहॉं पर हो रहे अवैध खनन से चैनेलाईजेशन को खतरा हो रहा है इस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए।	उद्योग विभाग (Geological wing)
4.	सभी बन्द पड़ी चैक पोस्टस (Integrated Check Posts) का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए।	Excise & Taxation/ पुलिस विभाग
5.	सचिव (law) सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी करने हेतु actual royalty बारे जॉंच करें ।	सचिव (law)
6.	जिला ऊना क्षेत्र में महिला पुलिस कर्मचारी को बंधक बनाने तथा छुरेबाजी की अपराधिक घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	पुलिस विभाग
7.	संतोषगढ़ क्षेत्र में सटटे की दुकानों में महिला पुलिस कर्मचारी को बंधक बनाया गया था। इस बारे पुलिस उचित कार्यवाही करे ताकि आम जनता का पुलिस पर / सरकार पर भरोसा बना रहे।	पुलिस विभाग
8.	जिला ऊना में रामलीला मैदान के सामने वाले निर्माणाधीन Boy स्कूल के नये भवन तथा मिनी सचिवालय ऊना के कार्य को पूर्ण करने के लिए शेष बची धनराशि को जारी किया जाए ताकि कार्यों को अविलम्ब पूर्ण किया जाए।	शिक्षा / राजस्व विभाग/ उपायुक्त ऊना
9.	तहसील वेलफेयर कार्यालय अम्ब का घनारी से ही सुचारू संचालन किया जाए।	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
10.	जिला ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर क्षेत्र के बेसहारा पशुओं/गायों की सुरक्षा के लिए गौ अभ्यारण्य का निर्माण पशु पालन विभाग के पास उपलब्ध 250 कनाल भूमि बरनोह/ बढ़ोह पर किया जाए। इसके निर्माण के लिए अच्छी व नवीनतम डिजाईन को तैयार किया जाए।	पशु पालन विभाग
11.	भोरंज निर्वाचन क्षेत्र की कुनाह खडड में 800 बीघा सरकारी भूमि की माईनिंग को तुरन्त प्रभाव से रोका जाए। साथ ही 2018 से पहले प्रदेश में सरकारी व निजी भूमि पर आबंटित की गई सभी माईनिंग लीज की विस्तृत रिपोर्ट नाम व जिलावार सूची सहित प्रस्तुत की जाए तथा वर्ष 2018 के बाद सरकारी व निजी भूमि पर ऑक्शन की माईनिंग लीज की भी विस्तृत रिपोर्ट नाम व जिलावार सूची सहित अतिशीघ्र प्रस्तुत की जाए और तब तक किसी भी प्रकार की माईनिंग अनुमति पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाए।	उद्योग विभाग (Geological wing)
12.	कुनाह खडड में कॉलेज से 150 मीटर, पुल से 15 मीटर तथा पीने के पानी की योजना से 150 मीटर की दूरी पर लगे एक क्रशर के कारण उपरोक्त तीनों स्थानों को खतरा पैदा हो गया है कृपया इस मामले में प्रमुख अभियन्ता तथा सम्बन्धित विभाग तुरन्त कार्यवाही करे।	लोक निर्माण/ जल शक्ति/उद्योग विभाग
13.	भोरंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भोरंज क्षेत्र तथा टौणीदेवी क्षेत्र की सीमाओं पर लगती पंचायतों के सब–डिवीजन को ठीक किया जाए।	उपायुक्त हमीरपुर

14.	भोरंज क्षेत्र से बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग में नियमों का सही प्रकार से पालन किया जाए साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार (NHAI) के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी शीघ्र आयोजित की जाए।	लोक निर्माण विभाग
15.	बस अडडा भोरंज के निर्माण के लिए हिमफैड की भूमि पर कृषि विभाग के स्टोर को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए ताकि शीघ्र कार्य आरम्भ हो सके।	बस अडडा प्राधिकरण / कृषि विभाग / हि0प्र0 सहकारी विपणन संघ
16.	हमीरपुर शहर में Police Command and Control Centre स्थापित किया गया है। इसके सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने लिए अतिरिक्त धनराशि लगभग रू0 30-40 लाख का प्रावधान पुलिस विभाग को करवाया जाए	राजस्व / परिहवन विभाग
17.	पॉलीक्लिनीक (Veterinary) हमीरपुर तथा लाहौल-स्पिति में भी खोला जाए।	पशु पालन विभाग
18.	प्रदेश में निर्मित सिंचाई की योजनाओं की जिलावार सूची तैयार की जाए जिसमें यह भी स्पष्ट किया गया हो कि ईतनी योजनाएं चालू (Functional) हैं, इतने क्षेत्र (Hectare) को सिंचाई प्रदान कर रही हैं तथा इतनी बन्द पड़ी हैं।	जल शक्ति विभाग
19.	लिंक रोड़ / सड़कों के निर्माण के समय गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए तथा सड़क बनने के बाद उसकी समय-सीमा तय होनी चाहिए साथ ही सड़क निर्माण के समय हर एक बारीकी का ध्यान रखा जाए और तय पैमानों (fixed norms/parameters) में किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए।	लोक निर्माण विभाग
20.	महाविद्यालय बड़सर में DP के पद को सृजित कर शीघ्र भरा जाए। ऑडिटोरियम तथा बाउन्ड्री वॉल का भी उचित प्रबन्ध किया जाए साथ ही MA (English & Commerce) की कक्षाएं भी आरम्भ की जाएं।	शिक्षा विभाग
21.	बड़सर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बनी धंगोटा-पनयाली पीने के पानी की योजना के लिए रू0 35 लाख का प्रबन्ध किया जाए ताकि निर्माण कार्य पूर्ण कर क्षेत्र की जनता को इसका लाभ प्रदान किया जा सके।	जल शक्ति/ SOMA Deptt.
22.	अस्थाई पुलिस चौकी बिझड़ी के लिए वन विभाग खाली पड़े भवन को पुलिस विभाग को प्रदान करे।	वन / पुलिस विभाग
23.	सराहन-चण्डीगढ़ सड़क की डी.पी.आर को दो भागों में शीघ्र तैयार किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
24.	यदि किसी भी योजना में एफ.सी.ए. मामले / वन आपत्तियां आती हैं/लगती हैं तो वन विभाग द्वारा यह आपतियां केवल एक बार ही आनी/लगनी चाहिए। साथ ही जिला स्तर पर गठित कमेटी के रूप में समस्त उपायुक्त प्रत्येक माह योजनाओं की समीक्षा कर लम्बित वन आपत्तियों का निपटारा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करें।	वन विभाग / समस्त उपायुक्त
25.	हिमाचल तथा उतराखण्ड की सीमा में यमुना नदी पर खनन की गतिविधियों के सम्बन्ध में बनाई गई कमेटी को पूरी शक्तियां प्रदान की जाएं ताकि एक-दूसरे की सीमा में अवैध खनन पर रोक लगाई जा सके।	उपायुक्त सिरमौर
26.	एफ.सी.ए. मामले में केन्द्र सरकार द्वारा कुछ तकनीकी आपत्तियां (AA&E and Sanction) लगाई जा रही हैं इनका शीघ्र समाधान किया जाए।	वन विभाग
27.	हिमाचल तथा उतराखण्ड को जोड़ने वाले पुल का निर्माण उतराखण्ड सरकार द्वारा किया जा रहा है इसकी पूरी कनेक्टीविटी के लिए हिमाचल प्रदेश की ओर से केवल 1 कि0मी0 की सड़क का निर्माण किया जाना है जिसके लिए विभाग द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग

28.	लोक निर्माण विभाग में ठेकेदारों द्वारा अच्छे–2 कार्यों को पूरा कर कठिन कार्य को छोड़ दिया जाता है ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। साथ ही डी.पी.आर. की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों/ अधिकारियों द्वारा तैयार की गई डी.पी.आर की संख्या, जॉंच की गई डी.पी.आर. की संख्या को उनकी ACR में नम्बर प्रदान करने बारे विभाग अमल करे।	लोक निर्माण / जल शक्ति विभाग/ सामान्य प्रशासन
29.	लोक निर्माण विभाग वाहनों की लोड क्षमता के आधार पर सड़कों की मोटाई पर, गुणवत्ता पर study करे। साथ ही पानी वाले ठण्डे क्षेत्रों में सीमेन्ट रोड़ बनाने पर भी ध्यान दे।	लोक निर्माण विभाग
30.	लोक निर्माण विभाग राज्य द्वारा निर्मित सड़कों तथा NHAI द्वारा निर्मित सड़कों के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार करे। पानी की पूरी निकासी नदी नालों तक सुनिश्चित करे।	लोक निर्माण विभाग
31.	प्रदेश के सरकारी स्कूलों में Toilets की स्वच्छता/मुरम्मत के लिए प्रधानाचार्य भी अपने स्कूल फण्ड से धन का प्रावधान करे। इस बारे प्रधानाचार्यों को उचित दिशा–निर्देश जारी किए जाएं।	शिक्षा/ प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
32.	निर्वाचन क्षेत्र कसौली के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र काम्बली की सड़क को एनएच के साथ जोड़ने के लिए रू0 2.5 करोड़ जारी किए जाएं और कार्य शीघ्र आरम्भ /पूर्ण किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
33.	जल शक्ति विभाग डैम की डी.पी.आर. बनाने से पहले पॉवर कॉरपोरेशन या किसी Dam Safety Organisation से सर्वे तथा स्टडी जरूर करवाए।	जल शक्ति विभाग
34.	सड़क दुर्घटना/ अन्य दुर्घटना में अस्पताल द्वारा मृत व्यक्ति का पोस्ट मार्टम परिजनों की सहमति से आरम्भ करने का निर्देश दिया जाए। साथ ही शव परिजनों को तभी दिया जाएगा जब पुलिस वहां उपस्थित होगी। दुर्घटना घटित क्षेत्र की पुलिस अस्पताल में जाए या अन्य थाने की पुलिस वहां पहुंच कर मामले का निपटान करे इस बारे कोई सरलीकरण / हल किया जाए।	स्वास्थ्य / पुलिस विभाग
35.	विधायकों द्वारा VKVNY के माध्यम से जब भी पंचायतों को धनराशि जारी की जाती है तो पंचायतों को 10 दिन में टैण्डर लगाना होगा व 15 दिन में कार्य अवार्ड करना होगा। यदि पंचायत प्रधान ऐसा नहीं करते तो बी.डी.ओ. 15 दिन बार स्वतः ही उपरोक्त कार्य को कर सकता है। एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया जाए जो निर्धारित धनराशि के टैण्डर लगाने तथा अवार्ड करने हेतु बी.डी.ओ. को शक्तियां deligate करे / शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करे।	योजना विभाग
36.	साई कोठी–I तथा II के बिजली बोर्ड के कार्यालयों के कर्मचारियों को डेपयूटेशन के आधार पर HPPCLtd. में जहां जाना चाहता है वहां भेज दिया जाए बशर्ते कि कोई भी सरपल्स स्टाफ में न जाए।	HPSEBLtd./ HPPTCLtd.
37.	क्षेत्र में फैली हिमोफिलीया बीमारी के फैक्टर 4 तथा 8 के टीके अविलम्ब उपलब्ध करवाने हेतु मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए जाएं। साथ ही सीएमओ स्तर पर भी यह टीके लगाए जाएं और सूचीबद्ध निजी ऐजैन्सियों से भी इसकी खरीद करने के दिशा–निर्देश जारी किए जाएं।	चिकित्सा शिक्षा /स्वास्थ्य विभाग
38.	13 कि0मी0 की मणिमहेश यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यात्रा के आधे स्थान पर (6 कि0मी0 पर) Community Centre का निर्माण किया जाए जिसमें Toilets, Sheds, Food arrangement, Health and Rescue Camps इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा सकें।	पंचायती राज विभाग/ उपायुक्त चम्बा
39.	प्रदेश में पहाड़ों की खाली पड़ी जगह पर फलदार पेड़–पौधे जैसे रसभरी, काफल, कैंथ, अखरोट, चिलगोजा, ठांगी इत्यादि लगाए जाएं।	वन/ उद्यान विभाग

40.	जिन विधायक प्राथमिकताओं की डी.पी.आर. तैयार कर दी गई है उन्हें भी प्रतिस्थापित करने के लिए negotiation करने बारे विभाग विचार करे।	योजना विभाग
41.	चम्बा तथा पठानकोट बस डिपो के स्टाफ का rationalization किया जाए।	HRTC/ परिवहन विभाग
42.	हरियाणा से लगती सीमा टिम्बर ट्रेल के साथ बनासर में जो बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं इस बारे विभाग उचित कार्यवाही करे।	राजस्व विभाग
43.	सभी उपायुक्त जब भी एफसीए की बैठक करें तो सम्बन्धित माननीय विधायकों को भी बैठक में आमन्त्रित करें और हर महीने / हफते होने वाली बैठकों की तिथियां भी सुनिश्चित की जाएं तथा लोक निर्माण विभाग के नोडल अधिकारियों का आना भी सुनिश्चित करेंगे।	समस्त उपायुक्त
44.	लोक निर्माण विभाग जिला बिलासपुर के बझवाणी पुल के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण करे।	लोक निर्माण विभाग
45.	कोलडैम से पानी की एक बड़ी योजना 15-16 पंचायतों के लिए बनी है लेकिन कन्दरौर पुल के पास एक पाईप की सप्लाई को दो पाईपों में डाइवर्ट किया गया है जिससे दबाब कम हो जाता है और पूरा पानी पंचायतों तक नहीं पहुंच पा रहा है इस बारे में विभाग सम्बन्धित माननीय विधायक के साथ बैठकर इसका समाधान करे।	जल शक्ति विभाग
46.	सभी विधायक अपनी विधायक निधि से मुख्यमंत्री लोक निर्माण भवन के कार्यों को पूर्ण करने के लिए धनराशि का सहयोग करें और योजना विभाग इस बारे VKVNY दिशा-निर्देशों में उचित संशोधन करे।	समस्त माननीय विधायक/ योजना विभाग
47.	नशे पर पूर्ण रोक लगाने के उददेश्य से प्रदेश के सभी सरकारी/निजी स्कूलों में कक्षा 5 से 10 के लिए एक पाठ्यक्रम (lesson) शामिल किया जाए।	शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
48.	श्री नैनादेवी जी के प्राथमिक विद्यालय बाग-चंगयाणा की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
49.	33 के.वी. सब स्टेशन नैनादेवी जी के कार्य को तीव्रगति से पूरा किया जाए।	HPPTCLtd./ HPSEBLtd.
50.	रौंग-टौंग हाईड्रो प्रोजेक्ट Private Party को दे दिया जाए।	HPPTCLtd./ HPSEBLtd.
51.	लाहौल स्पिति के चीचम में Wind Energy का सर्वे करवाया जाए।	HPPTCLtd./ HPSEBLtd./ ऊर्जा विभाग
52.	वन विभाग द्वारा रिक्त/खाली पड़ी भूमि को DPF में convert करने से पहले मुख्यमंत्री से अनुमति ली जाए।	वन / राजस्व विभाग
53.	उर्दू में लिखी गई अधिसूचनाओं/अभिलेखों को हिन्दी में अनुवाद करने के लिए अनुवादक के कुछ पद भरे जाएं।	राजस्व विभाग
54.	1952 की वन विभाग की अधिसूचना को चैलेंज किया जाए।	वन विभाग
55.	सचिव (विधि), हि०प्र० सरकार भी DPF का पूरा अध्ययन करे। साथ ही खनन से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण / (mining lease) की एक तय सीमा तथा उसके बाद उस भूमि का मालिकाना हक उसके परिवार को वापिस करने बारे भी अध्ययन करे।	सचिव (विधि),
56.	सभी अधिकारियों/उपायुक्तों को एक दिशा-निर्देश जारी किया जाए जिसमें NHAI द्वारा assets के लिए जो धनराशि राज्य खाते में दी गई है को व्यय करने बारे स्पष्टता की गई हो।	प्रशासनिक सचिव (लोक निर्माण विभाग)
57.	सभी अधिकारियों को एक दिशा-निर्देश जारी किया जाए जिसमें Reserve Forest में सड़क बनाने के लिए एफसीए से सम्बन्धित स्पष्टता प्रदान की गई हो।	वन विभाग

58.	निर्वाचन क्षेत्र इन्दौरा में पिछले 3-4 वर्षों से खनन से प्राप्त होने वाली वार्षिक रायल्टी की तथा डमटाल मन्दिर से आने वाली वार्षिक लीज मनी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	उद्योग विभाग/ उपायुक्त /State Geologist
59.	री कॉलेज के निर्माणाधीन दो भवनों में पहले एक भवन के कार्य को पूर्ण कर कक्षाएं आरम्भ की जाएं तथा उसके बाद दूसरे निर्माणाधीन भवन के कार्य तीव्रगति से पूर्ण किया जाए।	शिक्षा विभाग
60.	प्रदेश के जिन स्कूलों के भवन निर्माण के टैण्डर हो चुके हैं या जो भवन पूर्ण निर्माण की स्थिति में हैं उनकी एक सूची बनाकर प्रस्तुत की जाए ताकि इन स्कूलों को आगामी बजट में शामिल किया जा सके।	शिक्षा विभाग
61.	रैण पुलिस चौकी को थाना बना दिया गया है जब तक इसका नया भवन निर्मित नहीं होता तब तक इसके साथ लगते पुराने अस्पताल के भवन से ही इसका संचालन करने बारे पुलिस विभाग कार्यवाही करे।	पुलिस विभाग
62.	निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर की PMKSY के तहत लम्बित 86-86 करोड़ रूपये की सिंचाई की दो डीपीआरज़ को शीघ्र केन्द्र से स्वीकृत करवाया जाए।	जल शक्ति विभाग
63.	विस्थापित लोगों को जिन्हें DC Land (District Comissioner's authorization) दी गई थी परन्तु अब वह Forest Land कर दी गई है कैसे ? और जिन विस्थापित लोगों को अन्य राज्य में भूमि प्रदान की गई है क्या वे हिमाचल में 2-3 बिस्वा भूमि के हकदार हैं या नहीं इस बारे, साथ ही जैसे विस्थापितों (प्रोजेक्टस/एनएच/अन्य कारणों से) को मुआवजा प्रदान कर दिया गया है क्या वे भी भूमि के पात्र हैं, इस बारे पूरी study कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।	वन / राजस्व/ उपायुक्त कांगड़ा/ सचिव(विधि)
64.	निर्वाचन क्षेत्र जसवां-परागपुर के राजकीय तकनीकी महाविद्यालय जंडौर के भवन में IIT की कक्षाएं चलाने बारे सचिव, निदेशक से बात करे।	सचिव(शिक्षा)
65.	बिजली की तारों को ओवरहैड या अंडरग्राउंड करने के लिए विधायक निधि से विद्युत विभाग को धन देने बारे विभाग कार्यवाही करे।	योजना विभाग
66.	मुख्यमंत्री लोक भवन के निर्माण के लिए विधायक निधि से धन देने बारे विभाग कार्यवाही करे।	योजना विभाग
67.	ज्वालामुखी क्षेत्र के 3 पुलों सिधौड़ापतन, अमतर मैदान के सामने तथा जन्दराह-माड़ के निर्माण कार्य पूर्ण किए जाएं।	लोक निर्माण विभाग
68.	तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए पलम्बर तथा फिटर के ट्रेडों में दाखिले की अनिवार्यता +2 की जाए।	तकनीकी शिक्षा विभाग
69.	प्रदेश में अगल सत्र से ए.एन.एम. की ट्रेनिंग/कार्स को बन्द किया जाए।	स्वास्थ्य/ चिकित्सा शिक्षा विभाग
70.	सचिव (विधि), हि०प्र० सरकार, NGT के आदेशों को जिसमें रोहतांग में वाहनो की क्षमता निर्धारित है को न्यायालय में अपील करे और इसमें वाहनों की संख्याा में बढ़ोतरी करने तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधियां करने बारे अपील करे।	सचिव (विधि) / उपायुक्त कुल्लू
71.	निर्वाचन क्षेत्र मनाली में पतलीकूहल सीएचसी तथा सर्किट हाउस मनाली के लिए नगर एवं ग्राम योजना विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करे।	नगर एवं ग्राम योजना विभाग
72.	स्वास्थ्य विभाग के सभी deputations को निरस्त किया जाए।	स्वास्थ्य विभाग
73.	मनाली निर्वाचन क्षेत्र में बरसात में क्षतिग्रस्त लिंक सड़कों को बस योग्य संचालन हेतु ठीक करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता कार्यवाही करे और की गई कार्यवाही से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवाए।	लोक निर्माण विभाग
74.	प्रदेश में लो वोल्टेज की समस्या को हल करने और Quality of light प्रदान करने के लिए विभाग एक अध्ययन(Study) करे।	HPSEBLtd./ HPPTCLtd.

75.	बंजार निर्वाचन क्षेत्र में बन रहे दलासनी पुल को शीघ्र निर्मित किया जाए।	लोक निर्माण विभाग
76.	ठेकेदारों को दिए गये कार्यों तथा उन्हें कितने समय में पूरा किया गया, गुणवत्ता कैसी है के आधार पर श्रेणी / वर्गों में विभाजित किया जाए।	लोक निर्माण / जल शक्ति/ समस्त सम्बन्धित विभाग
77.	बंजार बाईपास निर्माण के लिए शेष भूमि का अधिग्रहण तथा डिमार्केशन के लिए उपायुक्त, तहसीलदार को आदेश कर सम्बन्धित मामले में कार्यवाही करे।	उपायुक्त कुल्लू
78.	आनी निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सीए स्टोर को सूची में शामिल किया जाए।	उद्यान/कृषि विभाग
79.	उपायुक्त महोदय, सरकार द्वारा निर्धारित 38 रू0 प्रति लीटर दूध की कीमत को लागू करने बारे कार्यवाही करे।	उपायुक्त कुल्लू
80.	लोक निर्माण, जल शक्ति अन्य विभागों के अधिकारियों (CEs, SEs, and XEN) द्वारा कितनी-2 योजनाओं को उनके निर्माणाधीन स्थान पर जाकर जांचा गया, क्या कार्यवाही की इत्यादि के हिसाब से उनकी ACR में Entry की जाए।	लोक निर्माण / जल शक्ति/ समस्त सम्बन्धित विभाग
81.	Eco-Tourism में चौपाल विधान सभा तथा लगते क्षेत्रों जैसे चूड़धार, सरांह, नौहराधार, हरिपुरधार इत्यादि को विकसित किया जाए।	पर्यटन / वन विभाग
82.	चौपाल से खिड़की सड़क लगभग 16 कि0मी0 को 10 मीटर की चौड़ाई के साथ सुधारा जाए।	लोक निर्माण विभाग
83.	ठियोग तथा चौपाल अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाई जाए।	स्वास्थ्य विभाग
84.	नारकण्डा में बन रहे स्केटिंग रिंक के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए बजट का उचित प्रावधान किया जाए।	युवा खेल सेवाएं / वन/ पर्यटन विभाग
85.	ननखड़ी के जरोल टिक्कर जो नशे का गढ़ बनता जा रहा है पर विशेष ध्यान दिया जाए।	पुलिस विभाग
86.	प्रदेश में बनने वाले सभी सीए स्टोरों के लिए पूर्व अनुमति ले ली जाए।	उद्यान विभाग
87.	करसोग निर्वाचन क्षेत्र की सेरी-कटाण्डा-महोग सड़क डंगों को पूरा कर बसों की आवाजाही के लिए चालू की जाए।	लोक निर्माण विभाग
88.	प्राथमिक पाठशाला देवीधड़ में लगने वाली सुरक्षा दीवार का निर्माण शीघ्र किया जाए।	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
89.	वन विश्राम गृह जाच्छ के निर्माण कार्य का ऑडिट करवाया जाए।	वन विभाग
90.	सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष इस बारे अधिसूचना जारी करें कि जिन विश्राम गृहों का निर्माण आरम्भ नहीं हुआ है उन्हें रोक दिया जाए और जब तक पुराने विश्राम गृहों को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक प्रदेश में किसी भी विभाग का कोई नया विश्राम गृह नहीं बनाया जाएगा और प्रदेश के सभी विश्राम गृहों में एक समान किराये की शर्त को लागू किया जाए।	समस्त प्रशासनिक सचिव/ समस्त विभागाध्यक्ष
91.	प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों तथा आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में बिजली की निर्बाध /सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में उचित दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएं।	चिकित्सा शिक्षा/ स्वास्थ्य विभाग/ HPSEBLtd./
92.	योजना विभाग बल्ह निर्वाचन क्षेत्र की कलखर-रत्ती सड़क की डी. पी.आर. को नाबार्ड से शीघ्र स्वीकृत करवाए।	योजना विभाग
93.	बल्ह निर्वाचन क्षेत्र की ढांगू कूहल की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए जिसमें प्रतिवर्ष धन खर्च करने पर भी जनता को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिलता।	जल शक्ति विभाग
94.	जल शक्ति विभाग में जिन-2 योजनाओं के लिए बजट नहीं है उनकी रिपोर्ट प्रेषित की जाए।	जल शक्ति विभाग

95.	प्रदेश के लोगों को जो मनरेगा में कार्यरत हैं और बढ़ाए गये 16 रुपये नहीं मिले हैं उन्हें 15 अगस्त, 2023 से एरियर के साथ दिहाड़ी/शेष राशि प्रदान की जाए।	ग्रामीण विकास विभाग
96.	बल्ह निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत बढियाल में किशोर नामक व्यक्ति का मकान पूरा चला गया उसे मिला 1 लाख रू0 और साथ वाले भाई का मकान नहीं गिरा उसे मिले 3 लाख रू0, सुखराम नामक व्यक्ति का नुकसान हुआ उसे मिले 10 हजार रू0 तथा जिसका कुछ नहीं गया उसे मिला 40 हजार रू0 इस बारे उचित कार्यवाही की जाए।	मुख्य सचिव/ ग्रामीण विकास/ पंचायती राज विभाग/ उपायुक्त मण्डी
97.	सभी प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष दिनांक 05 फरवरी, 2024 तक निर्वाचन क्षेत्रवार तथा वर्षवार यह रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि पिछले कुछ वर्षों में किन–2 योजनाओं/भवनों का शिलान्यास किया गया, कितना बजट प्रावधान रखा गया, कितनों में कार्य आरम्भ हुआ या नहीं, कितनों में कार्य पूर्ण हुआ, कितनों में कार्य पूर्ण करने हेतु कितने धन की आवश्यकता है। इस मुददे को मुख्य सचिव अपने स्तर पर पूरा करे।	समस्त विभाग / मुख्य सचिव
98.	स्वास्थ्य विभाग इस मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि कितने मरीजों पर कितने चिकित्सक होने चाहिए।	स्वास्थ्य विभाग

***

(अनुबन्ध 'क')

वार्षिक बजट (2024–25) के लिए माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए माननीय विधायकों के साथ दिनांक 29 तथा 30 जनवरी, 2024 को होने वाली बैठकों के लिए माननीय मुख्य मन्त्री, श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खु का उद्घाटन भाषण।

---

1. मैं, समस्त प्रतिभागियों का वार्षिक योजना वर्ष 2024–25 के लिए राज्य की प्राथमिकताओं पर चर्चा हेतु आयोजित इस बैठक में स्वागत करता हूँ।

2. इस बैठक में होने वाले विचार विमर्श तथा परामर्श से हमें प्रदेश में विकास की दिशा तय करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। हम प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा समाज के सभी वर्गों के त्वरित व सन्तुलित विकास के प्रति वचनबद्ध हैं। मैं आपकों सूचित करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने इस उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज मानकर इसके प्रभावी कार्यन्वयन के लिए दृढ़ संकल्प से कार्य कर रही है।

3. राज्य सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए ईमानदारी से कार्य कर रही है, जहाँ महिलाओं, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों सहित समाज के सभी वर्गों को उचित सम्मान मिल रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के एक साल के दौरान आम जन के उज्ज्वल भविष्य के लिए कई ऐतैहासिक फैसले लिए गये हैं।

4. कार्यभार संभालने के बाद वर्तमान सरकार, एक नियमित सरकार की तरह काम न करके इस उददेश्य से कार्य कर रही है कि हमारी नीतियां और कार्यक्रम कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए।

5. सत्ता संभालने के बाद गत एक वर्ष में वर्तमान सरकार द्वारा तीन गारंटियां पूरी की गई हैं। इनमें सबसे पहले बिना कोई राजनैतिक लाभ सोचे पहली ही कैबिनेट बैठक में पुरानी पैंशन योजना (OPS) लागू कर दी गई।

6. प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से उभरने के लिए हमारी सरकार द्वारा युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए 680 करोड़ रूपये की राजीव गाँधी स्वरोजगार स्टार्ट–अप योजना के पहले चरण के तहत ई–टैक्सी योजना शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को ई–टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सीडी प्रदान कर रही है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उददेश्य से एवं युवाओं को एक निश्चित आय प्राप्त हो सके इसके लिए सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में ई–टैक्सियों का अनुबन्ध आधार पर संचालन हेतु पोर्टल तैयार कर पंजीकरण शुरू कर दिया गया है।

7. मनरेगा श्रमिकों की दिहाड़ी 212 रूपये से बढ़ाकर 240 रूपये कर प्रदेश में नौ लाख पात्र लोगों को इसका लाभ प्रदान किया है जिनमें 65 फीसदी महिलाएं हैं । जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी 266 से बढ़ाकर 294 रूपये की गई है।

8. राज्य सरकार ने चार हजार (4,000) अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ स्टेट' के रूप में गोद लिया, उनके कल्याण के लिए कानून बनाया और मुख्य मंत्री सुख–आश्रय कोष की स्थापना कर योजना शुरू की। इसके तहत राज्य सरकार 27 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनकी देखभाल और उच्च शिक्षा के लिए उचित सहायता प्रदान कर रही है।

9. किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दूध के खरीद मूल्य में 6 रूपये की बढ़ोतरी की।

10. पिछले मानसून के दौरान राज्य को इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। केन्द्र सरकार से कोई भी विशेष पैकेज न मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के साथ 4500 करोड़ रूपये के विशेष पैकेज का प्रावधान किया। प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता मिल सके इसके लिए घरों के निर्माण के लिए सरकारी दरों पर सीमेंट के बैग के अतिरिक्त मुफ्त बिजली, पानी कनेक्शन और गैस सिलेण्डर प्रदान किए गये। इसके साथ ही प्रभावितों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 और शहरी क्षेत्रों में 10,000 रूपये किराये के रूप में दिया जा रहा है।

11. हमारा प्रयास रहेगा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी व उत्तरदायी प्रशासन प्रदान किया जाए। राज्य सरकार भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता की नीति अपना रही है। जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने एवं कुशल प्रशासन प्रदान करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। व्यवस्था में परिवर्तन के जरिए सभी लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे।

12. हमारी सरकार ने वार्षिक योजना 2024–25 के आकार को रू0 9989.49 (नौ हजार नौ सौ नवासी दशमलव चार नौ) करोड़ प्रस्तावित किया है।

13. हाल हीं में वर्ल्ड बैंक के साथ 2,000 करोड़ की लागत का समझौता हस्ताक्षर किया गया है जिससे हिमाचल में जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विकास कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों में कार्य किया जाएगा।

14. वर्ष 2023–24 के दौरान नाबार्ड से 918.81 करोड़ रूपये (नौ सौ अठारह दशमलव ईक्यासी करोड़) की जिसमें लोक निर्माण विभाग की 62 (बासठ) एवं जल शक्ति विभाग की 93 (तिरान्वे) विधायक प्राथमिकताएं स्वीकृत करवाई जा चुकी हैं। मार्च माह तक नाबार्ड से और अधिक विधायक प्राथमिकताओं को स्वीकृत करवाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है।

15. माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को सामान्यतः नाबार्ड संचालित RIDF कार्यक्रम से Finance किया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं को सर्वप्रथम केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषित करने का प्रयास किया जाता है।

16. आप सभी प्रदेश की प्रमुख समस्याओं से भली भान्ति परिचित हैं। आवश्यकता है कि हम इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए संतुलित योजनाएं तैयार करें तथा इनके कार्यान्वयन को गति प्रदान करें। मैं, सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी विकास कार्यक्रमों के संचालन में सरकार को सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे।

17. आगामी बजट (2024–25) की इन निर्धारित बैठकों में माननीय विधायकों की विधायक प्राथमिकताएं प्राप्त करने के लिए प्रपत्र–। में संशोधन किया गया है। इस संशोधित प्रपत्र–। में प्रत्येक माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित केवल पांच प्राथमिकताएं प्रस्तावित कर सकते हैं। मुख्य विकास शीर्षो (वास्तिविक नई स्कीमें RNS), क्रमशः सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई योजनायें, ग्रामीण पेयजल / मल निकासी योजनाएं की एक–एक स्कीम अथवा किसी एक मद में तीन / दो प्राथमिकताएं प्रस्तावित की जा सकती हैं। उपरोक्त शीर्षो में रख रखाव से सम्बन्धित एक प्राथमिकता तथा एक ही प्राथमिकता परिवहन विभाग के अन्तर्गत ईलैक्ट्रिक बस चलाने हेतु चार्जिंग स्टेशन सहित (किसी एक रूट पर जहां पहले से HRTC की डीजल बस चल रही हो) शामिल कर सकते हैं।

18. चूंकि R.I.D.F. नाबार्ड के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण योग्य गतिविधियां ही पात्र हैं और शहरी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आर.आई.डी. एफ. के तहत नाबार्ड धन का प्रावधान नहीं करता है। अतः नगर निगमों के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण, वित्त पोषण के लिए एवं विषम क्षेत्रीय विकास की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा सम्बन्धित माननीय विधायकों से प्राथमिकताएं मांगकर UIDF (Urban Infrastructre Development Fund) के तहत वित्त पोषण के लिए भेजी जाएंगी।

19. सभी माननीय विधायकों से अनुरोध है कि वह अपनी विकास योजनाओं की सूचना यदि निर्धारित प्रपत्र पर इस बैठक में उपलब्ध न करवा सकें तो अतिशीघ्र योजना विभाग को अलग से भिजवा दें ताकि उन्हें आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित किया जा सके। मेरा समस्त प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों से भी अनुरोध है कि वे माननीय विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं / शिकायतों को निपटाने में किसी प्रकार की कोताही न बरतें तथा उनके बहुमूल्य सुझावों पर अमल करें। विशेषतः लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग से आग्रह रहेगा कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 918.81 (नौ सौ अठारह दशमलव ईक्यासी) करोड़ के बजट परिव्यय का पूर्ण उपयोग करें और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति (reimbursement) दावे दिनांक 15 मार्च, 2024 से पहले जमा करें।

20. माननीय विधायकों द्वारा दी गई योजनाओं की डी.पी.आर. के बनने में होने वाले विलम्ब को कम करने के लिए FCA/FRA/Gift deed आदि औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से निराकरण के लिए मैं निर्देश देता हूँ कि सम्बन्धित विभाग और उपायुक्त भी अपने स्तर पर हर महीने प्राथमिकताओं की समीक्षा करेंगे जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए।

21. आपको प्रेषित प्राथमिकताओं के प्रपत्र–। के साथ हमने प्रपत्र–।। भी संलग्न किया है जिसमें प्रदेश की विकास नीति, वित्तीय संसाधन जुटाने, मितव्ययता, बेहतर प्रशासन, स्वरोजगार व रोजगार सृजन इत्यादि महत्वपूर्ण मुददों पर सुझाव मांगे गए हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इन विषयों पर भी अपने बहुमूल्य सुझाव बैठक में रखें।

22. मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि वर्तमान राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन पर केन्द्रित है और इस सम्बन्ध में एक वर्ष में हमारी सरकार ने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत नींव रखी है और वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर राज्य का एक आदर्श बन जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष एवं आने वाले समय में सरकार आम आदमी, किसानों और युवाओं से जुड़ी योजनाएं लाएगी।

23. मैं, इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध करता हूँ कि बारी–बारी से सभी माननीय विधायक अपने बहुमूल्य विचार इस बैठक में रखें।

***

माननीय विधायकों के साथ निर्धारित बैठकों की संशोधित जिलावार समय सारणी

क्रं. सं.	जिले का नाम (निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या)	दिनांक	समय
1.	1. ऊना (5) 2. हमीरपुर (5) 3. सिरमौर (5)	29-01-2024	पूर्वाहन् 10.30 से 1.30 बजे
2.	1. सोलन (5) 2. चम्बा (5) 3. बिलासपुर (4) 4. लाहौल व स्पीति (1)	29-01-2024	अपराहन् 2.00 से 5.00 बजे
3.	1. कांगड़ा (15) 2. किन्नौर (1) 3. कुल्लू (4)	30-01-2024	पूर्वाहन् 10.30 से 1.30 बजे
4.	1. शिमला (8) 2. मण्डी (10)	30-01-2024	अपराहन् 2.00 से 5.00 बजे

***

माननीय मुख्य मन्त्री, हि0प्र0, की अध्यक्षता में विधायक प्राथमिकता की दो दिवसीय बैठकों में जिलावार / चुनाव क्षेत्रवार भाग लेने वाले माननीय मन्त्री एवं माननीय विधायकों का ब्यौरा ।

क्र. सं.	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम	पदनाम
1.	2.	3.	4.	5.
29–01–2024 (प्रातः 10:00 बजे से 1:30 बजे तक)				
1.	ऊना	1. गगरेट	श्री चैतन्य शर्मा	माननीय विधायक
		2. हरोली	श्री मुकेश अग्निहोत्री	माननीय उप मुख्यमंत्री
		3. ऊना	श्री सतपाल सिंह सत्ती	माननीय विधायक
		4. कुटलैहड़	श्री दविन्द्र कुमार (भुटटो)	माननीय विधायक
2.	हमीरपुर	1. भोरंज	श्री सुरेश कुमार	माननीय विधायक
		2. हमीरपुर	श्री आशीष शर्मा	माननीय विधायक
		3. बड़सर	श्री इन्द्र दत्त लखनपाल	माननीय विधायक
		4. नदौन	श्री सुक्खविन्द्र सिंह सुक्खू	माननीय मुख्य मन्त्री
3.	सिरमौर	1. पच्छाद	श्रीमति रीना कश्यप	माननीय विधायिका
		2. नाहन	श्री अजय सोलंकी	माननीय विधायक
		3. पांवटा	श्री सुख राम चौधरी	माननीय विधायक
29–01–2024 (सांयः 2:00 बजे से 5:00 बजे तक)				
4.	सोलन	1. अर्की	श्री संजय अवस्थी	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
		2. नालागढ़	श्री के.एल. ठाकुर	माननीय विधायक
		3. दून	श्री राम कुमार	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
		4. सोलन	डॉ0 धनी राम शॉंडिल	माननीय मंत्री (स्वास्थ्य)
		5. कसौली	श्री विनोद सुल्तानपुरी	माननीय विधायक
5.	चम्बा	1. चुराह	श्री हंस राज	माननीय विधायक
		2. भरमौर	डॉ0 जनक राज	माननीय विधायक
		3. चम्बा	श्री नीरज नैययर	माननीय विधायक
		4. डलहौजी	श्री डी.एस. ठाकुर	माननीय विधायक
6.	बिलासपुर	1. झण्डूता	श्री जीत राम कटवाल	माननीय विधायक
		2. घुमारवीं	श्री राजेश धर्माणी	माननीय मंत्री(तकनीकी शिक्षा)
		3. बिलासपुर	श्री त्रिलोक जम्वाल	माननीय विधायक
		4. श्री नैना देवी जी	श्री रणधीर शर्मा	माननीय विधायक

7.	लाहौल–स्पीति	1. लाहौल–स्पीति	श्री रवि ठाकुर	माननीय विधायक
30–01–2024 (प्रातः 10:00 बजे से 1:30 बजे तक)				
8.	कांगड़ा	1. नूरपुर	श्री रणबीर सिंह	माननीय विधायक
		2. इन्दौरा	श्री मलेन्द्र राजन	माननीय विधायक
		3. फतेहपुर	श्री भवानी सिंह पठानिया	माननीय विधायक
		4. ज्वाली	श्री चन्द्र कुमार	माननीय मंत्री (कृषि)
		5. देहरा	श्री होशियार सिंह	माननीय विधायक
		6. जसवां–प्रागपुर	श्री बिक्रम सिंह	माननीय विधायक
		7. ज्वालामुखी	श्री संजय रतन	माननीय विधायक
		8. जयसिंहपुर	श्री यादविन्द्र गोमा	माननीय मंत्री(आयुष)
		9. शाहपुर	श्री केवल सिंह	माननीय विधायक
		10. बैजनाथ	श्री किशोरी लाल	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
9.	किन्नौर	1. किन्नौर	श्री जगत सिंह नेगी	माननीय मंत्री (राजस्व)
10.	कुल्लू	1. मनाली	श्री भुवनेश्वर गौड़	माननीय विधायक
		2. कुल्लू	श्री सुन्दर सिंह ठाकुर	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
		3. बन्जार	श्री सुरेन्द्र शौरी	माननीय विधायक
		4. आनी	श्री लोकेन्द्र कुमार	माननीय विधायक
30–01–2024 (सांयः 2:00 बजे से 5:00 बजे तक)				
11.	शिमला	1. चौपाल	श्री बलबीर सिंह वर्मा	माननीय विधायक
		2. ठियोग	श्री कुलदीप राठौर	माननीय विधायक
		3. कसुम्पटी	श्री अनिरूद्ध सिंह	माननीय मंत्री (पंचायती राज)
		4. शिमला–ग्रामीण	श्री विक्रमादित्य सिंह	माननीय मंत्री(लोक निर्माण)
		5. जुब्बल–कोटखाई	श्री रोहित ठाकुर	माननीय मंत्री (शिक्षा)
		6. रामपुर	श्री नन्द लाल	माननीय विधायक
		7. रोहड़ू	श्री मोहन लाल बराकटा	माननीय मुख्य संसदीय सचिव
12.	मण्डी	1. करसोग	श्री दीप राज	माननीय विधायक
		2. नाचन	श्री विनोद कुमार	माननीय विधायक
		3. बल्ह	श्री इन्द्र सिंह	माननीय विधायक
		4. सरकाघाट	श्री दलीप ठाकुर	माननीय विधायक

***